page 1 and 8 June 7_page 1 Mar 25 final ds.qxd 6/7/2026 1:15 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 एमए स्टेडियम में आयोजित हुई अस्मिता सिटी वूमेन साइक्लिंग लीग 2026

5 श्रेयस अय्यर बने काबुनी के सुपर कोच, क्रिकेट प्रशिक्षण को मिलेगा तकनीक का साथ

8 छात्रों को करियर, उद्यमिता और पेशेवर विकास के गुर बताए

मौसम जम्मू — न्यूनतम 28 — अधिकतम 42

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-138 | जम्मू तवी, रविवार 07 जून, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को और गति देने पर प्रधानमंत्री मोदी ने की चर्चा

नई दिल्ली, 6 जूनी। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शनिवार को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के सदस्यों के साथ बैठक कर वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को और अधिक गति देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के सदस्यों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री और परिषद के सदस्यों ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक प्रगति को और मजबूत करने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर विस्तार से चर्चा की। उच्चस्तरीय बैठक में लोगों के जीवन को आसान बनाने (ईज ऑफ लिविंग) तथा व्यापार करने की सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुधारों पर भी विचार-विमर्श किया गया। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र संस्था है, जो भारत सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक तथा संबंधित विषयों पर सलाह प्रदान करती है। बैठक में प्रधानमंत्री के दो प्रमुख सचिव P K Mishra और Shaktikanta Das भी परिषद के

> परिषद के सदस्यों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव का भी अपना आकलन साझा किया। विशेष रूप से ऊर्जा बाजारों, व्यापारिक मार्गों और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर इसके असर पर चर्चा की गई

सदस्यों के साथ उपस्थित रहे। परिषद के सदस्यों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव का भी अपना आकलन साझा किया। विशेष रूप से ऊर्जा बाजारों, व्यापारिक मार्गों और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर इसके असर पर चर्चा की गई। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक व्यवधानों, महंगाई के दबाव और असमान विकास दर जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों से आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम करने और टिकाऊ विकल्प अपनाकर भारत की आर्थिक मजबूती में योगदान देने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से जहां संभव हो, घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) को प्राथमिकता देने, ईंधन की खपत कम करने, एक वर्ष तक अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचने, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने, खाद्य तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती अपनाने और सोने की खरीद में संयम बरतने का आग्रह किया।ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, मेट्रो रेल सेवाओं, कार-पूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक उपयोग और माल परिवहन के लिए रेलवे पर अधिक निर्भरता बढ़ाने का भी आह्वान किया।

जावेद राणा ने जम्मू संभाग में ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता और बाढ़ तैयारी उपायों की समीक्षा की

जेजेएम योजनाओं और एसएएससीआई आपदा कार्यक्रम कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश

जम्मू, 06 जून। जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज जम्मू संभाग में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आई एंड एफसी) विभागों की ग्रीष्मकालीन तैयारियों की समीक्षा के लिए एक व्यापक बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने मानसून से पहले निर्बाध जलापूर्ति और प्रभावी बाढ़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।आगामी गर्मी के चरम महीनों में जल संकट से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करते हुए जावेद राणा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जलापूर्ति योजनाएं पूर्ण क्षमता से संचालित हों और उनकी रोकथाम संबंधी मरम्मत कार्य पहले से ही पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि पेयजल उपलब्धता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी ताकि सेवाएं निर्बाध बनी रहें। मंत्री ने अधिकारियों को उभरती जल संकट स्थितियों पर त्वरित और सक्रिय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष हस्तक्षेप करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संकट वाले क्षेत्रों की संख्या कम करने और भीषण गर्मी के दौरान निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं।

मंत्री ने मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को इनके उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई आधारभूत संरचना विकसित करते समय पुरानी योजनाओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रभावी कार्यप्रणाली विश्वसनीय जलापूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

मंत्री ने पूर्णता के करीब पहुंच चुकी जेजेएम योजनाओं पर कार्य में तेजी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के चरम मौसम से पहले इन योजनाओं को समय पर शुरू किया जाए ताकि लोगों को बिना देरी लाभ मिल सके।

जावेद राणा ने अधिकारियों को वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए जिला स्तर पर व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नवाचार आधारित उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा।

जम्मू संभाग में मरम्मत योग्य हैंडपंपों की जानकारी लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मरम्मत योग्य इकाइयों को गर्मी के चरम समय से पहले बहाल किया जाए।

बैठक के दौरान मुख्य अभियंता जल शक्ति (आई एंड एफसी) जम्मू ने प्रस्तुति के माध्यम से विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों, भविष्य की योजनाओं और आकस्मिक योजना की जानकारी दी।

खबर संक्षेप

पॉक्सो मामले में समझौता कराने के आरोप में एसएचओ समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित

सांबा, 6 जून जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज एक मामले में कथित रूप से समझौता कराने के आरोपों के बाद पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुज कुमार ने मामले की जांच के आदेश देते हुए रामगढ़ पुलिस स्टेशन के एसएचओ सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रामगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह, एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) और दो सहायक उप-निरीक्षकों (एएसआई) को जांच पूरी होने तक निलंबित कर जिला पुलिस लाइन (डीपीएल) से अटैच कर दिया गया है।

एसएसपी ने आरोपों की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए विस्तृत जांच के आदेश जारी किए हैं। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि मामले के निपटारे में किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर अजय सिंह चिब को रामगढ़ पुलिस स्टेशन का नया स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) नियुक्त किया है। इसके अलावा संबंधित घटनाक्रम में एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) का तबादला गोरान पुलिस चौकी में कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि संवेदनशील पीओसीएसओ मामले के संचालन को लेकर पुलिस विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर को नशा-मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई

> नशा-मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान 19वें जिले तक पहुंचा, उपराज्यपाल ने किश्तवाड़ में पदयात्रा का नेतृत्व किया

हम नशे के कारोबार की हर कड़ी को तोड़ रहे हैं

जम्मू, 6 जून। उपराज्यपाल Manoj Sinha ने शनिवार को कहा कि, हम नशे के व्यापार की हर कड़ी को तोड़ रहे हैं। चाहे वे सीमा पार के तस्कर हों, नशा विक्रेता हों या आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाले लोग — किसी को भी सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा। हमारी एजेंसियां हर नार्को-आतंकवादी का पीछा कर रही हैं और उनके नेटवर्क को स्थायी रूप से नष्ट कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले लगभग दो महीनों में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश भर में पदयात्राओं में भाग लिया, प्रभावित परिवारों के दुख-दर्द को साझा किया और युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य नशे के दुरुपयोग के खिलाफ जमीनी स्तर पर जन-आंदोलन खड़ा करना और नार्को-आतंकवाद का अंत करना है। उपराज्यपाल किश्तवाड़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यह अभियान अब तक जम्मू-कश्मीर के 19 जिलों तक पहुंच चुका है, जिससे गांवों और कस्बों से नशे को समाप्त करने के सामूहिक संकल्प को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा, पिछले 56 दिनों से मैं इस धरती से हर नशा तस्कर और नार्को-आतंकवादी को समाप्त करने के मिशन पर कार्य कर रहा हूं। चाहे वे पुलवामा, रामबन, कुलगाम या किश्तवाड़ में हों, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने वालों के लिए कोई दया नहीं होगी। उपराज्यपाल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में नार्को-आतंकवादियों के लिए कोई नरमी नहीं है।

उन्होंने कहा, जो लोग नशे की लत से बाहर निकलकर सामान्य जीवन में लौटना चाहते हैं, उन्हें हर संभव सहायता और सम्मान के साथ पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। लेकिन जो नार्को-आतंकवादी दूसरों की बर्बादी से लाभ कमाते हैं, उनके लिए कोई दया नहीं हो सकती। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है — नार्को-आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जबकि निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उपराज्यपाल ने कहा कि यद्यपि नशा-मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान 100 दिनों के लिए निर्धारित है, लेकिन यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत मात्र है। उन्होंने कहा, यह कुछ सप्ताहों की लड़ाई नहीं बल्कि वर्षों का युद्ध है। विजय के लिए पूरे समाज की चौबीसों घंटे एकजुट प्रतिबद्धता आवश्यक है। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम जम्मू-कश्मीर की धरती को नशा तस्करों और नशा विक्रेताओं से पूरी तरह मुक्त करेंगे।

वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन के डिब्बे में दरार, कोई घायल नहीं

लुधियाना,6 जून। शनिवार को दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लुधियाना रेलवे स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही समय बाद ट्रेन के एक स्लीपर कोच में दरार आ गई और उसका एक हिस्सा शौचालय के पास से अलग हो गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह घटना ट्रेन के एस-2 कोच में हुई। कोच की संरचना में खराबी आने के कारण शौचालय के निकट का हिस्सा धंस गया। कोच का ढांचा टूटने से शौचालय की सीटों सहित कुछ फिटिंग्स रेलवे ट्रैक पर गिर गईं। घटना चिंताजनक होने के बावजूद किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन के चलना शुरू करते ही उन्हें अचानक जोरदार झटका महसूस हुआ, जिससे कुछ समय के लिए ट्रेन के पटरी से उतरने की आशंका पैदा हो गई।

जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी में नवनियुक्त सिविल जजों के लिए पूर्व-नियुक्ति प्रशिक्षण शुरू

श्रीनगर, 6 जून। जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी ने आज अपने श्रीनगर परिसर में 39 नवनियुक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए पूर्व-नियुक्ति प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश Arun Palli ने किया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश Sanjeev Kumar, न्यायमूर्ति Rajnesh Oswal तथा अन्य न्यायाधीश उपस्थित रहे।

उद्घाटन भाषण में न्यायमूर्ति अरुण पाली ने न्यायिक सेवा को एक सार्वजनिक विश्वास बताते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज आम नागरिकों के लिए न्यायपालिका का चेहरा होते हैं।

उन्होंने नव-नियुक्त अधिकारियों से उच्चतम नैतिकता, विनम्रता और निष्पक्षता बनाए रखने तथा निरंतर सीखते रहने की अपील की।

मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार ने कहा कि न्यायिक सेवा में ईमानदारी, निष्पक्षता, अनुशासन और करुणा आवश्यक हैं। उन्होंने तकनीक के जिम्मेदार उपयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक निर्भरता से बचने की सलाह दी।

न्यायमूर्ति राजनेश ओस्वाल ने बार से बेंच तक के परिवर्तन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि न्यायाधीश का सर्वोच्च दायित्व संविधान और कानून के प्रति निष्ठा है।

न्यायिक अकादमी के निदेशक नसीर अहमद डार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों और संरचना की जानकारी दी।

टीईटी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है :सकीना

श्रीनगर 6 जून। जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने शनिवार को कहा कि सरकार ने जम्मू और कश्मीर के शिक्षकों से संबंधित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है और उनके हितों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। एक बयान में इटू ने कहा कि सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य किया है और मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धता के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। सरकार इस मामले को लगातार आगे बढ़ा रही है और हमारे शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को जिम्मेदारीपूर्वक और सक्रिय रूप से संभाल रही है और ठोस उपायों के माध्यम से इस मामले पर लगातार नज़र रख रही है। जम्मू और कश्मीर के शिक्षकों से संबंधित टीईटी मुद्दे पर सरकार ने हमेशा जिम्मेदारीपूर्वक और सक्रिय रूप से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले को लगातार उठाया है और उससे भी महत्वपूर्ण

बात यह है कि हमने इस पर ठोस कार्रवाई भी की है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पहले ही पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी थी और संबंधित अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग ने 26 मई, 2026 के एक पत्र के माध्यम से अपने स्थायी वकील को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले भी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ है। उन्होंने कहा कि हम अपने शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू तवी-मुंबई सीएसएमटी सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन का संचालन

जम्मू, 06 जून। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने जम्मू तवी से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) तक सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन संख्या 04602 चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन 7 जून, 2026 को रात 12:30 बजे जम्मू तवी से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3 बजे मुंबई सीएसएमटी पहुंचेगी। यह पूर्णतः आरक्षित सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन होगी, जिसमें कुल 21 कोच लगाए गए हैं। ट्रेन की संरचना में 2 फर्स्ट एसी कम्पोजिट, 12 थर्ड एसी, 1 सेकंड एसी, स्लीपर तथा 2 दिव्यांगजन सहित सामान्य श्रेणी के कोच शामिल किए गए हैं, जिससे विभिन्न वर्गों के यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिल सके। यात्रियों की सुविधा के लिए यह ट्रेन मार्ग में पठानकोट जंक्शन, जालंधर कैंट, लुधियाना जंक्शन, अंबाला कैंट, दिल्ली सफदरजंग, मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, बीना जंक्शन, भोपाल जंक्शन, इटारसी जंक्शन, भुसावल जंक्शन, मनमाड जंक्शन, नासिक रोड, कल्याण जंक्शन और दादर स्टेशनों पर ठहरेगी। रेलवे ने लुधियाना, अंबाला कैंट, आगरा कैंट, झांसी, भोपाल, इटारसी और भुसावल स्टेशनों पर ट्रेन की तकनीकी जांच (सीटीएस) तथा जल आपूर्ति (वाटरिंग) की विशेष व्यवस्था भी की है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की समय-सारणी और आरक्षण की स्थिति की पुष्टि करने की अपील की है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सीआरपीएफ जवान समेत दो हिरासत में, राइफल व 50 कारतूस बरामद

बारामुला, 06 जून । जम्मू-कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने कनिस्पोरा क्षेत्र में देर रात नाका चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक 12-बोर राइफल और 50 कारतूस बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, कनिस्पोरा-जाहामा क्रॉसिंग पर एसओजी बारामूला और 52 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) की संयुक्त टीम द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान जम्मू पंजीकरण संख्या जेके02डीएन-6527 वाली एक बलेनो कार को रोका गया। वाहन में सवार दो व्यक्तियों की पहचान सिकंदर खान (32) पुत्र नजीर अहमद खान निवासी गिंगल उरी तथा वकील अहमद ठाकरी (40) पुत्र नूरदीन ठाकरी निवासी कमलकोट उरी के रूप में हुई।प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वकील अहमद ठाकरी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में जवान के पद पर कार्यरत हैं। वह पहले 218 बटालियन, छत्तीसगढ़ में तैनात थे और हाल ही में उनका स्थानांतरण 237 बटालियन, राजस्थान में हुआ था। हालांकि, उन्होंने अभी तक नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। वहीं, सिकंदर खान स्थानीय निवासी है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि दोनों आरोपित पिछले दो दिनों से वाहन लेकर इलाके में घूम रहे थे। चेकिंग के दौरान वाहन और उसमें सवार व्यक्तियों की तलाशी लेने पर एक 12-बोर राइफल और 50 कारतूस बरामद किए गए। मौके पर मौजूद टीम ने मामले की सूचना एसएचओ बारामूला को दी, जिसके बाद दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए जीआईसी बारामूला लाया गया। बाद में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें बारामूला पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया।

जम्मू और कटरा से 111 टन से अधिक चेरी रेल मार्ग से भेजी गई

जम्मू,, 06 जून। जम्मू-कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध चेरी को देशभर के बाजारों तक तेजी और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल की पहल सफल साबित हो रही है। चालू सीजन में अब तक जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशनों से एसएलआर/वीपी आधारित रेल परिवहन के माध्यम से 111 टन से अधिक चेरी देश के विभिन्न हिस्सों में भेजी जा चुकी है।

किसानों और बागवानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा परिवहन लागत कम करने के उद्देश्य से रेलवे विशेष सुविधाएं प्रदान कर रहा है। चेरी जैसे शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए विशेष कोचों का उपयोग किया जा रहा है जिससे समय पर और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है। इस अवसर पर उचित सिंघल ने कहा कि रेलवे किसानों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी बागवानी उत्पादों के परिवहन के लिए विशेष सुविधाएं जारी रखी जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री ने सब्ज़ी मंडी लेन सतवारी से डिगयाना-जीवन नगर पुल परियोजना का व्यापक किया निरीक्षण

जम्मू, 06 जून । उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आज सब्ज़ी मंडी लेन सतवारी, जम्मू से डिगयाना-जीवन नगर पुल परियोजना का व्यापक निरीक्षण किया और इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना पर चल रहे कार्यों की गति और गुणवत्ता की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर पर हुई प्रगति का आकलन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए पुल का समय पर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना क्षेत्र में संपर्क सुधारने और जन आवागमन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बाद में उपमुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी विरासत परिसर का दौरा किया और विरासत स्थल पर चल रहे जीर्णोद्धार और

विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने ऐतिहासिक गदाधर मंदिर के प्रभावित लॉन और दीवारों के जीर्णोद्धार की समीक्षा की। उन्होंने जीर्णोद्धार कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन को सुनिश्चित करते हुए परिसर के विरासत स्वरूप और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री ने विरासत परिसर और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए आवश्यक नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता का भी जायजा लिया। जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अंधेरी गली मोहल्ला, पंजतीर्थी, मुबारक मंडी और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उपमुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विरासत धरोहरों के संरक्षण और जन सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने अधिकारियों को निकट समन्वय में कार्य करने और जनता की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान करने का निर्देश दिया। जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री के साथ थे।

दांपत्य के वास्तविक गहने

स्त्री के सौंदर्य *गहने*

प्राचीन काल से ही स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने में गहनों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। बिना साज-श्रृंगार और आभूषणों के स्त्री सौंदर्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पर उन गहनों से अलग भी कुछ गहने ऐसे है जो सोने-चांदी या हीरे-मोती से बने तो नहीं होते पर उन गहनों से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है वे।

खोते नहीं अपनी चमक

ये गहने ऐसे होते है जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती और जिनका चलन भी नहीं बदलता, जबकि बाह्य आभूषणों का चलन हमेशा बदलता रहता है। उन गहनों में से ही एक है- स्त्री का शालीन व्यवहार। जी हां, अच्छा व्यवहार और सलीका एक ऐसा अद्भुत अलंकरण होता है जो साधारण-सी स्त्री को भी असाधारण और आकर्षक बना देता है।

शालीन व्यवहार एक अहम गहना

आप कितनी भी फैशनेबल गहनों से लकदक हों लेकिन आपके बोलने, उठने-बैठने के अंदाज में शालीनता का अभाव हो तो आपके पहने गहने व्यक्तित्व में चार चांद लगाने के बजाय चांद उतारते नजर आएंगे। यूं तो सलीका और शिष्टता किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, किंतु किसी भी स्त्री के लिए अपने पति के दिल की चिरस्थाई साम्राज्ञी बनने के लिए शालीनता एक अहम गहना होता है। पति और पूरे परिवार की दुलारी बनने में सलीका और शालीनता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है।

कोर्टशिप के दौरान अथवा विवाह के आरंभिक दौर में तो आपकी हर अदा अपने प्रियतम को दीवाना बनाने के लिए काफी होती है। उन दिनों आप अपने जीवनसाथी को रिझाने और सम्मोहित करने के लिए उर्वशी, मेनका और रम्भा के सारे हथकंडे अपनाने से नहीं चूकतीं। आपकी मनमोहक अदाओं का जादू उन पर सर चढ़ कर बोलने लगता है। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ आपके हाव-भाव और स्टाइल में अनजाने ही ऐसे परिवर्तन आने लगते है कि शुरुआती दिनों की वह खुमारी ताजिंदगी एक 'हैगओवर' बन कर र ह जाती है। ऐसा सबके साथ नहीं होता। विशेषकर आज के युग में जब मीडिया के माध्यम से इतने तरह-तरह के नुस्खे परोसे जा रहे है तो कोई भी जागरुक स्त्री भला उन्हे आजमाने से क्यों चूकेंगी। फिर भी यदि आप से कहीं भी कुछ चूक हो गई है तो आज से ही संभल जाइए। फायदे की सलाह हो तो लेने में क्या हर्ज है।

ऐसा भी न करे

संवर कर हाथ में चाय की प्याली थामे चूड़ियां खनकाती हुई अपने पति को जगाती थीं। तब वे अलसाई आंखों से आपकी अदाओं पर रीझते हुए अखबार व चाय की चुस्कियों का आनंद लेते थे।

अब आप सुबह उठती है, उलझे और बेतरतीब बालों का घोंसला बनाए, आंखों को मिचमिचाते हुए पति को चाय पकड़ाती है। पति आप पर उचटती नजर डालकर अखबार में सिर गड़ा लेते है। आप बेडरूम से अटैच्ड बाथरूम में ब्रश करती है और ब्रश करते-करते मुंह पर झाग लपेटे पति के पास आकर कोई जरूरी बात करने लगती है। खाने की टेबल पर समय की कमी के कारण ताबड़तोड़ खाना ठूंसती है। मुंह से खाने की आवाज निकालती है। खाने के बाद जोर-जोर से डकार लेने लगती है।

जम्हाई आने पर आस-पास बैठे लोगों का ध्यान रखे बिना मुंह फाड़कर बिना हाथ या रूमाल रखे जम्हाई लेती है।

उम्र का ध्यान रखते हुए परिधानों का चयन करिए। षोडशी बाला की तरह चुस्त व तड़क-भड़क के रंगीन कपड़े कहीं आपको मजाक का पात्र न बना दें।

यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि जैसे पहले आप अपने पहनावे को लेकर सजग थीं वैसी ही अब भी रहिए। पहनावे का सलीका उम्र का मोहताज नहीं है।

वजन बढ़ जाने पर भी नाभि-दर्शना साड़ी का मोह नहीं त्याग पा रही हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा।

आपको शर्ट और मिनी ड्रेसेज पहनने का शौक है भले ही वे आपके शरीर पर फब नहीं रही हों।

अगर आप इनमें से कोई भी बात अमल में ला रही हों तो कृपया आज ही से उन पर विराम लगा दें। इस बात का इंतजार न करे कि पति ने तो कुछ टोका ही नहीं फिर लोगों की चिंता क्यों करे।

बनाए रखें बेडरूम की गरिमा

उम्र बढ़ने के साथ अधिकांश महिलाएं शयन कक्ष की संवेदनशीलता का अर्थ खोने लगती है। उन्हे लगता है कि अब बच्चे बड़े हो गए, इतनी उम्र हो गई, अब क्या शयनकक्ष और क्या उसकी प्राइवेसी?

लेकिन वे भूल जाती है कि हमारे शास्त्रों में भी स्त्री के पांच प्रमुख गुणों में एक गुण 'शयनेषु रम्या' पर बहुत जोर दिया है। शयन कक्ष ही वह मनोरम कक्ष है जहां दंपती अपने प्रारंभिक दिनों को बार-बार जीने के लिए प्रयास करते है।

कुछ स्त्रियां समय के साथ-साथ बाहरी कपड़ों और एक्सेसरीज पर तो ध्यान देती है लेकिन अपने इनरवेयर और नाइटी वगैरह में कटौती करने लगती है। लेकिन अब इन नुस्खों को भी अपना कर देखिए। आज भी आप वैसे ही इनरवेयर पहन कर देखिए जैसे आप पहले पहनती थीं। तितली के पंखों से नाजुक और खूबसूरत अंतर्वस्त्र निश्चय ही आपके पति के मूड को बदल देंगे।

अगर नाइटी पुरानी है तो बदल दें। उसकी जगह मुलायम झीने कपड़ों की फ्रिल लगी मुलायम नाइटी पहन कर देखिए। आप अपने को तरोताजा महसूस करने लगेंगी। आपके पहनावे पर आपका ही नहीं आपके पति का मूड भी निर्भर करता है, न यकीन हो तो हमारी सलाह अपना कर देखिए।

वजन बढ़ने पर आप अकसर पैर फैलाकर नब्बे डिग्री का कोण बनाकर सोती है। आपको तो निस्संदेह आराम मिलता होगा लेकिन देखने वालों को आपकी यह मुद्रा बहुत बेआरामी में डाल सकती है। सिर्फ बैठते-चलते समय ही नहीं बल्कि सोते समय भी पोस्चर पर ध्यान दें।

यूं तो खर्राटों पर किसी का भी वश नहीं है किंतु कोशिश कर के करवट बदल कर कुछ हद तक इन पर काबू पाया जा सकता है।

अपनाएं अरोमाथेरेपी को

शरीर की स्वच्छता के साथ-साथ उसे सुगंधित रखने की अपनी पुरानी आदत को बनाए रखें। अरोमाथेरेपी का दांपत्य जीवन में चामत्कारिक असर होता है। न हो तो अपना कर देखें।

यह ध्यान रखें कि अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाकर, अपनी खूबियों को बरकरार रख कर आप अपने वास्तविक आभूषणों को धारण कर सकती है। ये गहने ऐसे होते है जिनके न खोने का डर रहता है न ही फीके पड़ने का। पहनने वाले आभूषण रहे या न रहे लेकिन इन वास्तविक आभूषणों के न रहने पर आप वास्तव में आभूषणविहीन हो जाएंगी।

11 टिप्स जिससे घर का हर कोना रहे रोशन

घर में प्राकृतिक रोशनी, ताजी हवा और धूप का सही ढंग से आना बहुत जरूरी है। यह तभी संभव है, जब मकान बनवाते समय सही ढंग से प्लानिंग की जाए। आपकी इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए इंटीरियर डिजाइनर एस. शर्मा दे रहे हैं कुछ खास सुझाव

1. मकान में अच्छी रोशनी हो, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि प्लॉट खरीदते समय आप इस बात का ध्यान रखें वह कम से कम तीन तरफ से खुला हो।

2. हर कमरे में बड़ी खिड़किया और इनके ऊपर ओवर हेड वेंटिलेटर होना चाहिए, जिनके ऊपर ग्लास लगा हो। इससे घर में प्राकृतिक रूप से रोशनी आती रहेगी।

3. डाइनिंग स्पेस, लिविंग एरिया या लॉबी के पिछले हिस्से में स्लाइडिंग ग्लेज डोर लगवाना भी बेहतर विकल्प है। इसे बंद करने के बाद भी घर के भीतर हल्की रोशनी आती रहती है।

4. किचन में भी ऐसी बड़ी खिड़की होनी चाहिए, जिसमें शीशे के अलावा जाली के दरवाजे की भी व्यवस्था हो।

5. बेडरूम के लिए वे विंडो सबसे अच्छी रहती है, इसमें खिड़की के ऊपर छज्जा होता है और खिड़कियां बाहर की ओर खुलती हैं। इससे कमरे में बारिश का पानी नहीं आता और खिड़की से पर्याप्त हवा और रोशनी आती है।

6. बाथरूम में भी दो से सवा दो फुट की टिंटेड ग्लास वाली खिड़की एग्जॉस्ट फैन के साथ होनी चाहिए।

7. बेसमेंट में प्राकृतिक रोशनी पहुंचाने की सही तरीका यह है कि भूतल से चार फुट ऊपर जाकर वहीं वेंटीलेटर की व्यवस्था की जाए। इससे पूरे बेसमेंट एरिया में रोशनी के साथ सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा भी मिलती है।

8. बेसमेंट एरिया में सन पाइप के जरिए भी प्राकृतिक रोशनी पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। इसमें रिफ्लेक्टिव पाइप द्वारा छत से कमरे तक प्राकृतिक रोशनी पहुंचाई जाती है, लेकिन काफी महंगी होने के कारण भारत में इस तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता।

9. घर के पैसेज एरिया में ट्रांसपेरेंट एस्बेस्टस शीट लगवा कर ग्लेज रूफ की व्यवस्था भी करवा सकती हैं, इससे आपके घर का यह हिस्सा खुला और हवादार दिखाई देगा।

10. अगर आपके घर में कोई ऐसा कमरा है, जिसकी दीवार की तरफ खिड़की बनाने की जगह नहीं है तो इसकी बीच की दीवार को हटाकर वहीं आप वुडन फ्रेम से बना ब्लॉक ग्लास वाला पार्टीशन वॉल लगवा दें। इससे आपके कमरे में पर्याप्त रोशनी पहुंच जाएगी।

11. रोशनी सभी को अच्छी लगती है, लेकिन मई-जून की तपती दुपहरी में यही रोशनी आंखों को चुभने लगती है। इससे बचने के लिए आप खिड़कियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगवाएं। इसके अलावा आप लाइनिंग वाली कर्टन्स या मोटी ब्लाइंड्स की व्यवस्था कर सकती हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

जवाहर नगर में 1.62 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

जम्मू, 06 जून (हि.स.)। जम्मू पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए विधायक अरविंद गुप्ता ने शनिवार को वार्ड नंबर-40, जवाहर नगर में 1.62 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले प्रमुख विकास कार्यों के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। यह परियोजना तीन चरणों में पूरी की जाएगी जिसमें पहला चरण जम्मू नगर निगम द्वारा जारी बाढ़ पुनर्स्थापन निधि के तहत शुरू किया गया है।

इस अवसर पर विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा कि वार्ड-40 के कई क्षेत्रों में पिछले लगभग 25 वर्षों से आधारभूत ढांचे के उन्नयन की मांग लंबित थी। इन विकास कार्यों की शुरुआत से स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

उन्होंने जम्मू नगर निगम के आयुक्त देवांश यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित के प्रति उनकी सकारात्मक सोच और सहयोग से इन कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो सकी है। विधायक ने कहा कि शेष दो चरणों के कार्य चालू वित्तीय वर्ष में कैपेक्स फंड के तहत पूरे किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने स्थानीय निवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। लोगों ने सफाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी मांगें रखीं, जिनके समाधान का आश्वासन विधायक ने संबंधित विभागों के समन्वय से दिया।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है और विकास केवल सड़कों एवं नालियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बेहतर स्वच्छता, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी इसका हिस्सा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वार्ड-40 की सभी लंबित विकास आवश्यकताओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

एमए स्टेडियम में आयोजित हुई अस्मिता सिटी वूमेन साइक्लिंग लीग 2026, महिला खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

जम्मू, 06 जून (हि.स.)। साइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द्वारा साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में शनिवार को ऐतिहासिक एमए स्टेडियम जम्मू में अस्मिता सिटी वूमेन लीग 2026 का आयोजन किया गया। महिला खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों की 30 से अधिक महिला साइकिलिस्टों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के साथ विश्व साइकिल दिवस रैली का भी आयोजन किया गया जिसमें 60 से अधिक साइकिलिस्टों, फिटनेस प्रेमियों और साइक्लिंग समर्थकों ने हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, फिट जीवनशैली और साइकिल को पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के रूप में अपनाने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जम्मू पूर्व के विधायक युद्धवीर सेठी ने किया जबकि सम्मानित अतिथि के रूप में अनीसा नबी उपस्थित रहीं। दोनों अतिथियों ने महिला खेलों को बढ़ावा देने और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजकों की सराहना की। प्रतियोगिता को साइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के चेयरमैन एवं साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव रविंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि संगठन महिला खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और साइक्लिंग प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सब-जूनियर वर्ग में हिरण्या ने स्वर्ण पदक, अदिति ने रजत और प्राजनाथ ने कांस्य पदक हासिल किया। जूनियर वर्ग में कुमारी ज्योति ने स्वर्ण, चांदनी कुमारी ने रजत और वीवा शर्मा ने कांस्य पदक जीता। एलीट वर्ग में अनु तलवार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि हरप्रीत भल्ला ने रजत और पायल जैन ने कांस्य पदक प्राप्त किया।

जम्मू कश्मीर व्यवसायिक परीक्षा बोर्ड ने जीएनएम लेटरल एंट्री कोर्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किया आयोजित

श्रीनगर, 06 जून (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड ने आज जम्मू और श्रीनगर केंद्रों पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जीएनएम लेटरल एंट्री कोर्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया।

यह परीक्षा कश्मीर मंडल के श्रीनगर स्थित एस.पी. कॉलेज, एम.ए. रोड और जम्मू मंडल के जम्मू स्थित गवर्नमेंट एम.ए.एम. कॉलेज में आयोजित की गई जिसमें जम्मू-कश्मीर भर से कुल 463 उम्मीदवारों ने भाग लिया।

प्रवेश परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित संस्थान/कॉलेज प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से जम्मू-कश्मीर बीओपीईई की अध्यक्ष प्रोफेसर मीनू महाजन के मार्गदर्शन में पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। संबंधित संस्थानों और कॉलेजों के कर्मचारियों की सतर्क निगरानी में परीक्षा बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुई। अध्यक्ष ने सदस्यों, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और जम्मू-कश्मीर बीओपीईई के अधिकारियों के साथ मिलकर जम्मू और श्रीनगर के दोनों केंद्रों पर आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सक्रिय रूप से निगरानी की। उन्होंने संबंधित कॉलेजों के कर्मचारियों और संबंधित जिला मुख्यालयों में उपायुक्तों के समग्र पर्यवेक्षण में तैनात कर्मचारियों को परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए धन्यवाद दिया।

सेवा भारती जम्मू ने जेएमसी के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन

जम्मू, 06 जून (हि.स.)। सेवा भारती जम्मू द्वारा शनिवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) जम्मू के ब्लड बैंक के सहयोग से वेद मंदिर, अम्फल्ला स्थित सेवा भारती कार्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वयंसेवकों, समाजसेवियों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर मानव सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

आयोजकों के अनुसार, शिविर में लगभग 50 से 60 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदाताओं के इस योगदान से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी तथा कई लोगों का जीवन बचाने में मदद मिलेगी।

रक्तदान शिविर का संचालन जीएमसी जम्मू ब्लड बैंक की विशेषज्ञ चिकित्सकीय टीम की देखरेख में किया गया। इस दौरान रक्तदान से संबंधित सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया गया, जिससे रक्तदाताओं को सुरक्षित और सुगम वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

सेवा भारती जम्मू के पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के उपचार के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ऐसे शिविर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने बताया कि सेवा भारती जम्मू समाज सेवा और जनकल्याण के विभिन्न कार्यों में निरंतर सक्रिय है तथा भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सेवा, सहयोग और जनभागीदारी की भावना को प्रोत्साहित करती रहेगी।

आरनिया के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में मादक पदार्थों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जम्मू, 06 जून (हि.स.)। मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय अल्लाह में ऋनशीली दवाओं को ना कहेंऋ विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उप पुलिस अधिकारी (प्रोबेशन) कायसर मीर एसएचओ आरनिया, प्रभारी बीपीपी अल्लाह एसआई अजीत गोरका, प्रधानाचार्य रूप लाल, विद्यालय के कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे और व्यक्तियों, परिवारों और समाज पर इसके प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डाला। छात्रों को मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें सोच-समझकर निर्णय लेने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशीली दवाओं से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR SERVICES SELECTION BOARD
Muthi Akhnoor Road, Jammu/ Zam Zam Complex Rambagh, Srinagar
(www.jkssb.nic.in)
[redacted]

Subject: **Provisional Selection list for the Post of Head Assistant in Home Department, advertised vide Notification No. 06 of 2020 dated 29.12.2020 under Item No. 214.**

NOTIFICATION

Whereas, the Jammu and Kashmir Services Selection Board, vide Indent No. Home/GB/187/2019 Dated 24-10-2020 followed by Home/GB/187/2019 dated 18-12-2020, received (01) Post of Head Assistant from Home Department, advertised vide Notification No. 06 of 2020 dated 29.12.2020, under Item No. 214 as per the following category-wise break up:

Cadre of the post	Item No.	OM	SC	ST	OSC	ALC/IB	RBA	PSP	EWS	TOTAL
District Reasi	214	01	0	0	0	0	0	0	0	01

Whereas, the requisite qualification for selection against the post, as per the Indent is given as under:

Name of the Post	Requisite Qualification
Head Assistant	(i) Should be deemed to be Graduate from Defence Services/any recognized University. (ii) Should be retired JCO or equivalent rank from Navy Air Force. (iii) Should preferably have knowledge of Accounts. (iv) Should possess exemplary character as per his discharge book. (v) Should qualify entrance test as per prescribed syllabus.

Whereas, the J&K Services Selection Board, accordingly conducted an (OMR) based written examination for the post of Head Assistant on 02.02.2025. Based on the performance of the candidates in it, the Board, vide Notification No. JKSSB-COE0EXAM(UT)/3/2025-06 (7641035) dated 15.04.2025, published the result/score-sheet of the candidates.

Whereas, after the publication of Result/Score-sheet, the candidate falling under the consideration zone, were called for Document Verification conducted on 07.05.2025, followed by supplementary DV on 17.06.2025.

Whereas, vide Office Order No. 221-SSB of 2025 dated 14.07.2025, a selection committee was constituted for preparing the Selection List for **(01) post** of Head Assistant in Home Department.

Whereas, the said Selection Committee, upon careful scrutiny of the Indent/advertisement, prepared the Provisional Selection List for **(01) One Post** in accordance with the Merit/ Eligibility of the candidates as per the extant rules and same was placed in the board in its 348th meeting, held on 30.05.2026, which after due deliberations and consideration of the matter, approved its notification.

Now, therefore, the Provisional Selection List of the candidate for **(01) One** post of Head Assistant, Home department advertised vide Notification No. 06 of 2020 dated 29.12.2020, is hereby notified as per **"Annexure"-A** to this Notification. It is further notified that:

i. This Provisional Selection List shall be subject to outcome of the OAs/Writ Petition(s), if any, pending in the competent court of law.
ii. This shall also be subject to the outcome of any pending inquiry, involving candidate(s), figuring in this Provisional Selection List.
iii. This is a Provisional List and shall be subject to the change(s) as per the objections as may be received against it and mere figuring in it shall not confer any right to selection, which shall be finalized after examination of the objections based on merit.
iv. In case any candidate(s) is aggrieved with this Provisional Selection List, or intends to furnish any document/clarification regarding his withheld candidature, he/she may represent through the e-mail address ***homeselection2026@gmail.com*** within **(10) ten days from the date of this Notification, beyond which no representations whatsoever shall be entertained.** The representations in this regard shall necessarily include complete details of the candidate including Name, Address, Roll Number and Contact Number.

By Order.

DIP/J-3243/26
Dtd: 6-6-2026

Sd/-
(Khurshid Ahmad Sanai), JKAS
Secretary
J&K Services Selection Board

No. JKSSB-Scry/23/2025-03 (E-7731861) Dated **05**.06.2026

Annexure-A of Notification No. JKSSB-Scry/23/2025-03 (E-7731861) Dated 05.06.2026

Provisional Selection list for the post of Head Assistant, District Cadre, Reasi, Home Department, Advertised vide Notification No. 06 of 2020 dated 29.12.2020, Item No. 214

Selection List under OM Category

Sr. No.	Dy. No	Roll No	Candidates Name	Fathers Name	DoB	Category	Total Score	Selection Category	Address	QUALIFICATION	YEAR OF PASSING	NAME OF INSTITUTE	REMARKS/DEFICIENCY
1	[illegible]	[illegible]	SHOWKAT HUSSAIN LONE	MOHD MAQBOOL LONE	[illegible]	OM	64.50	OM	Srigufwara, Anantnag	B.A (Tourism)	2007	IGNOU	

Waiting List under OM Category

Sr. No.	
1	Post remained unfilled due to Non-availibility of suitable candidate

Sd/-
Khurshid Ahmad Sanai, JKAS
Secretary
J&K Services Selection Board

नगर पालिका कार्यालय के बाहर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन

जम्मू,, 06 जून (हि.स.)। आरएस पुरा कस्बे में स्थित नगर पालिका कार्यालय के बाहर सफाई कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांग की कि उनकी लंबित समस्याओं और मांगों का जल्द समाधान किया जाए।

वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते कस्बे के बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के ढेर लग गए हैं जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

राजौरी के जंगलों में चलाए जा रहे संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान ने चौदहवें दिन में किया प्रवेश

राजौरी, 06 जून (हि.स.)। राजौरी जिले के मांजकोट सेक्टर के गंभीर मुगलन और दोरिमाल के घने जंगलों में भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा चलाया जा रहा संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान चौदहवें दिन में प्रवेश कर गया है। सुरक्षा बल क्षेत्र में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश जारी रखे हुए हैं। सुरक्षा बलों को यात्रियों और स्थानीय लोगों के पहचान पत्रों की जांच करते और क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चलाते देखा गया। इस अभियान को ऑपरेशन शेरुवाली नाम दिया गया है और इसे खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था जिसमें क्षेत्र में संदिग्ध आतंकवादियों की उपस्थिति का संकेत मिला था। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य संदिग्धों को निर्धारित क्षेत्रों में फंसाना है जबकि तलाशी दल अपने अभियान को तेज कर रहे हैं। इस क्षेत्र के गने जंगलों में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है।

जम्मू में लगातार बिजली कटौती पर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई चिंता

जम्मू,, 06 जून (हि.स.)। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरूण गुप्ता ने जम्मू क्षेत्र में लगातार हो रही अनियमित और लंबी बिजली कटौती पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और उमस के बीच हो रही अघोषित बिजली कटौती से आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों, उद्योगों और छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 100 प्रतिशत स्मार्ट मीटर वाले क्षेत्रों में भी बिजली कटौती जारी है जबकि सरकार ने इन क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया था। अरुण गुप्ता ने कहा कि बिजली संकट के कारण औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो रहा है, छोटे व्यवसायों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा पेयजल जैसी आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने खराब हो चुके स्मार्ट मीटरों को तत्काल बदलने, भूमिगत बिजली केबलिंग परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा प्रीपेड बिलिंग प्रणाली लागू करने से पहले बिजली ढांचे को मजबूत करने की मांग की। उन्होंने प्रशासन से गर्मी के मौसम में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया

8वें वेतन आयोग के साथ डेली वेजर्स को न्यूनतम वेतन, नियमितीकरण एवं लंबित वेतन का लाभ दिया जाए

जम्मू,, 06 जून (हि.स.)। मूवमेंट कल्कि की महिला विंग की महासचिव सपना हिंदू ने जम्मू-कश्मीर सरकार तथा माननीय उपराज्यपाल प्रशासन से मांग की है कि प्रदेश में 8वें वेतन आयोग को लागू करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स और अस्थायी कर्मचारियों की वर्षों पुरानी समस्याओं का भी समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार नियमित कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है तो उन कर्मचारियों को भी न्याय मिलना चाहिए जो वर्षों से सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

सपना हिंदू ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन प्रदेश के हजारों डेली वेजर्स आज भी ऐसे हैं जो न्यूनतम वेतन, नौकरी की सुरक्षा और समय पर वेतन भुगतान जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि विकास और कर्मचारी कल्याण की बात तभी सार्थक होगी जब समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित श्रमिक वर्ग को भी समान महत्व दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है। घरेलू गैस सिलेंडर, खाद्य सामग्री, दूध, सब्जियां, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और परिवहन जैसी आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि हुई है। ऐसे में सीमित आय पर कार्य कर रहे डेली वेजर्स के लिए अपने परिवार का भरण-पोषण करना अत्यंत कठिन हो गया है।

उत्तर रेलवे

ई-टेंडर नोटिस

भारत गणराज्य की ओर से कार्यरत निम्नलिखित कार्यों/सेवाओं के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करते हैं। बोलीदाता केवल निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक ही अपनी मूल/संशोधित बोलियाँ प्रस्तुत कर सकेंगे। इन निविदाओं के विरुद्ध मैनुअल बोली स्वीकार नहीं की जाएगी तथा यदि कोई मैनुअल बोली प्राप्त होती है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ठेकेदार को इन निविदाओं के विरुद्ध ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति है। निविदा दस्तावेज़ शुल्क एवं जमानत राशि केवल पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान माध्यमों जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से ही जमा की जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, जमा रसीद, एफडीआर आदि के माध्यम से मैनुअल भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निविदा प्रकार: खुला
बोली प्रणाली: एकल पैकेट प्रणाली
निविदा अपलोड करने की तिथि:
बोली बंद होने की तिथि/समय: 30.06.2026 14:30
ई-टेंडर खोलने की तिथि एवं समय: 30.06.2026 14:30
1. क्रम संख्या: 1; **निविदा संख्या/सूचना संख्या:** 95265160
कार्य का नाम: Supply & commissioning of one Set of Hydraulic re-railing equipment.
अनुमानित लागत: Rs. 8662380
आर्नेस्ट मनी: Rs. 173250
बोली की बैधता: 90 दिन
निधि आवंटन संख्या: में 20427504 उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया **www.ireps.gov.in** पर लॉग-इन करें। **1939/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

डोगरी संस्था जम्मू ने गोवर्धन सिंह जम्वाल ने डोगरी भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण में योगदान को किया याद

जम्मू, 06 जून (हि.स.)। डोगरी संस्था जम्मू द्वारा डोगरी भवन, कर्ण नगर स्थित कुँवर वियोगी स्मृति सभागार में कुँवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं डोगरी भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के प्रतिष्ठित संरक्षक स्वर्गीय गोवर्धन सिंह जम्वाल की स्मृति में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों, साहित्यकारों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं, मित्रों एवं शुभचिंतकों ने उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की।

सभा को संबोधित करते हुए डोगरी संस्था जम्मू के अध्यक्ष ललित मगोत्रा ने गोवर्धन सिंह जम्वाल के निधन को जम्मू-

कश्मीर के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत के लिए बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि श्री जम्वाल डोगरी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक मूल्यों के समर्पित संरक्षक थे तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यरत संस्थाओं को उनका निरंतर सहयोग सदैव स्मरणीय रहेगा। प्रो. मगोत्रा ने कहा कि संस्था जब गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही थी, तब गोवर्धन सिंह जम्वाल ने कुँवर वियोगी स्मृति सभागार के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 20 लाख रुपये की उदार सहायता प्रदान कर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण, विनम्रता और दूरदर्शी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी। शोक सभा में उपस्थित वक्ताओं ने डोगरी भाषा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में श्री जम्वाल के अमूल्य योगदान को याद करते हुए उन्हें एक उदार, संवेदनशील और दूरदर्शी व्यक्तित्व बताया। वक्ताओं ने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति उनके अटूट सहयोग तथा क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को विशेष रूप से रेखांकित किया। कार्यक्रम का समापन दिवंगत आत्मा की शाश्वत शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की सामूहिक प्रार्थना के साथ हुआ।

संपादकीय

दूरदराज़ गांवों और बस्तियों को भी सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ बनाना अनिवार्य

यह अत्यंत आवश्यक है कि सुरक्षा बल आगामी श्री अमरनाथजी यात्रा के दौरान मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अभी से तैयारी प्रारम्भ करें। इस संदर्भ में दूरदराज़ के गांवों और बस्तियों को भी सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है, क्योंकि अतीत में आतंकवादियों ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बरती गई लापरवाही का लाभ उठाकर अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने का प्रयास किया है।

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों ने जम्मू-कश्मीर में, विशेषकर यात्रा अवधि के दौरान, शांति बनाए रखने में सकारात्मक परिणाम दिए हैं। इसलिए इस वर्ष भी इसी प्रकार के प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है, ताकि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके। यह यात्रा दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु लाखों श्रद्धालुओं के आगमन का प्रतीक है।

प्रत्येक वर्ष सरकार यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती करती है। इस वर्ष भी ऐसी खबरें सामने आई हैं कि बंगाल और असम में चुनाव ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था हेतु जम्मू-कश्मीर भेजा जाएगा। किंतु केवल अतिरिक्त जवानों की तैनाती पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ अन्य सभी आवश्यक कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

इसी दिशा में सेना ने एक सराहनीय पहल करते हुए रामबन जिले में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (एनएच-44) के आसपास स्थित कब्बी, गंधरी, खट्टर, मुगाला और भटनी गांवों के ग्राम रक्षा समूहों (वीडीजी) के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर तैयारी को मजबूत करना, सुरक्षा बलों के साथ समन्वय बढ़ाना तथा वार्षिक यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना था। यह यात्रा आस्था, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक मानी जाती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में फायरिंग की स्थिति, हथियारों के संचालन तथा फायर एंड मूवजैसी व्यावहारिक अभ्यास प्रक्रियाएं शामिल थीं, जिससे प्रतिभागियों को आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया देने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखने में सहायता मिल सके। इस प्रकार के कदम यात्रा के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं और वीडीजी के पुनर्जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं।

चूंकि यात्रा प्रारम्भ होने में अभी कुछ दिन शेष हैं, इसलिए सेना को चाहिए कि वह पूरे क्षेत्र में मौजूद सभी वीडीजी को इसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करे, ताकि इस स्वयंसेवी बल का अधिकतम उपयोग किया जा सके। यह बल उन क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने तथा राष्ट्रविरोधी तत्वों का मुकाबला करने में सहायक हो सकता है, जहां सुरक्षा बलों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम है। यद्यपि देखने में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वीडीजी की भूमिका सीमित है, किंतु वास्तव में उनकी मौजूदगी दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों के भीतर विश्वास उत्पन्न करती है तथा हिंसा फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

परिवर्तन के 12 वर्ष- संकल्प, सेवा और सिद्धि

कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक रणनीति का केंद्र बना। Production Linked Incentive (PLI) योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल सहित 14 रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिला, जिससे 5.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ।

डॉ. शिवानी कटारा

पिछले 12 वर्षों में भारत ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तनों का एक नया युग देखा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास ने केवल गति ही नहीं, बल्कि नई दिशा और नई चेतना भी प्राप्त की। आर्थिक सुधारों से लेकर डिजिटल क्रांति, राष्ट्रीय सुरक्षा से सामाजिक समावेशन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक भारत ने आत्मनिर्भरता, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा की ओर उल्लेखनीय यात्रा तय की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रारंभ हुई यह यात्रा आज विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय संकल्प में रूपांतरित होती दिखाई देती है।

आर्थिक सुधार और वित्तीय समावेशन

मोदी सरकार की शुरुआती और सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में वर्ष 2014 का मेक इन इंडिया अभियान प्रमुख रहा, जिसने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा प्रदान की। घरेलू उत्पादन, विदेशी निवेश और सरल नियमों के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा निर्माण और मोबाइल उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इससे रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिली।

इसी दौरान अंत्योदय के संकल्प के तहत आर्थिक समावेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को नई पहचान दी। 6.3 करोड़ से अधिक MSME उद्यमों को सहायता मिली। वहीं, जन धन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें 30.80 करोड़ खाते महिलाओं के नाम हैं। 36.73 करोड़ ग्रामीण खातों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान बना।

वर्ष 2017 में लागू GST को स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में माना जाता है। अनेक अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक राष्ट्र, एक कर की अवधारणा को मजबूत किया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी, कर आधार विस्तृत हुआ और राजस्व संग्रह अधिक व्यवस्थित बना। IMF के अनुसार भारत का GDP वर्ष 2014 के लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। भारत जापान को पीछे छोड़ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि Economic Survey 2025-26 ने FY26 में 7.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है।

कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक रणनीति का केंद्र बना। Production Linked Incentive (PLI) योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल सहित 14 रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिला, जिससे 5.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ। Ease of Doing Business, GST सुधार और डिजिटल पारदर्शिता के कारण 2025-26 में रिकॉर्ड 94.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। वहीं, नोटबंदी ने अल्पकालिक चुनौतियों के बावजूद डिजिटल भुगतान, औपचारिक अर्थव्यवस्था तथा काले धन, नकली मुद्रा और आतंक वित्तपोषण पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

वहीं, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना ने सहकारी संघवाद, तकनीक-आधारित शासन और प्रशासनिक दक्षता को नई मजबूती प्रदान की।

डिजिटल इंडिया, सामाजिक सशक्तिकरण और आधारभूत विकास

डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले दशक में भारत की आर्थिक और तकनीकी तस्वीर को व्यापक रूप से बदल दिया। भीम ऐप, आधार और PI जैसी पहलों ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाया, जहाँ आज विश्व के लगभग 49 प्रतिशत रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। UPI कई देशों में सक्रिय है, जबकि IMPS और FASTag ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को और गति दी। DBT, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल पारदर्शिता ने सरकारी योजनाओं में लीकेज कम किए तथा लाभार्थियों तक सहायता सीधे पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया।

स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहलों ने उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान की। इन योजनाओं ने युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को रोजगार खोजने वालों से रोजगार सृजित करने वालों में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और डिजिटल बाज़ार से जोड़कर नई पहचान प्रदान की।

सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जबकि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध हुई। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान ने बालिका शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता को राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप दिया। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब महिलाओं को धुएँ से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ ईंधन, बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की नई दिशा दी। तीन तलाक प्रथा पर रोक लगाकर मुस्लिम महिलाओं को समानता, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की नई सुरक्षा प्रदान की गई।

कृषि क्षेत्र में PM-KISAN योजना के माध्यम से 11 करोड़ किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष सहायता दी गई। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में पीएम गति शक्ति योजना के तहत 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 3.5 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें तथा तीव्र गति से विस्तारित राष्ट्रीय राजमार्गों ने देश की कनेक्टिविटी को नई ऊँचाइयाँ प्रदान कीं। नए हवाई अड्डों के निर्माण और 'उड़ान' योजना ने देश की हवाई कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार किया, जबकि वंदे भारत और तेजस जैसी आधुनिक ट्रेनों ने भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को नई गति दी।

शिक्षा क्षेत्र में 2014 के बाद 1,200 से अधिक नए विश्वविद्यालय, 10 नए IIT तथा 7 नए IIM स्थापित किए गए। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर सामाजिक न्याय के दायरे का विस्तार किया गया, जिससे आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को शिक्षा और रोजगार में नए अवसर प्राप्त हुए।

नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, कौशल-आधारित और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2025 तक 2.27 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है।ड्ढ, 5त्र, ड्रोन, साइबर सुरक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में 400 से अधिक आधुनिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। इंडिया AI मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन ने भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकियों का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। नई दिल्ली में आयोजित AI Impact Summit ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका को और सुदृढ़ किया।

वहीं, खेलो इंडिया अभियान ने युवाओं में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा दी। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10,000 से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी ने भारत की उभरती खेल प्रतिभा और फिट इंडिया विज़न को और मजबूत किया।

सुरक्षा, सांस्कृतिक और वैश्विक नेतृत्व

राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने अधिक स्पष्ट, आक्रामक और निर्णायक नीति अपनाई। उरी और पुलवामा आतंकी हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने आतंकवाद के प्रति भारत की कठोर रणनीति को विश्व के सामने स्थापित किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई सटीक कार्रवाई ने भारत की सामरिक क्षमता का परिचय दिया। अग्निपथ योजना ने युवाओं को सेना से जोड़ते हुए सशस्त्र बलों को अधिक युवा और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में पहल की। वहीं, वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राष्ट्रीय एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया।

नक्सली हिंसा का खात्मा और 'रेड कॉरिडोर' के सिमटने से नक्सल-मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हुई। सुरक्षा और विकास की समन्वित रणनीति ने प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुँच, आधारभूत सुविधाओं और जनविश्वास को मजबूत किया।

इसी अवधि में भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत के पुनर्जागरण को नई ऊर्जा मिली। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, गौतम बुद्ध सर्किट, केदारनाथ पुनर्विकास और सोमनाथ मंदिर परिसर के आधुनिकीकरण ने आध्यात्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक चेतना को सशक्त बनाया। राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम्' के राष्ट्रप्रेरक स्वरूप को रेखांकित करते हुए राष्ट्र गान के समानांतर दर्जा दिया गया।

नया संसद भवन आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर उभरा। वहीं, डॉ. भीमराव आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, राष्ट्र प्रेरणा स्थल और प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे संस्थानों ने भारत की ऐतिहासिक विरासत, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय गौरव को नई मजबूती दी।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल कीं। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला विश्व का पहला देश बना, जबकि मंगलयान मिशन ने भारत को सबसे कम लागत में मंगल तक पहुँचने वाले देशों की अग्रणी श्रेणी में स्थापित किया।

वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका पिछले वर्षों में लगातार सशक्त हुई है। सफल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी और ग्लोबल साउथ की प्रभावशाली आवाज़ के रूप में भारत ने नई पहचान बनाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना भारत की सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक बना। वहीं, वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत 100 से अधिक देशों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराकर भारत ने वैश्विक मानवीय सहयोग और जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

मोदी सरकार के 12 वर्ष भारत के अमृत काल की मजबूत आधारशिला के रूप में उभरे हैं। विकसित भारत 2047 का विज़न केवल आर्थिक प्रगति का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी, तकनीक-सक्षम, सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण का व्यापक संकल्प है। मतभेदों के शोर से परे, परिवर्तन की यह यात्रा स्वयं साक्षी है कि बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, विरासत और वैश्विक नेतृत्व की एक नई गाथा रची है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

ग्रेट निकोबार पर राजनीति बनाम राष्ट्रनीति

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भारत आज ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां आर्थिक शक्ति, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रमुख आधार बन चुके हैं। ऐसे समय में ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के हित में महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरी है। बावजूद इसके, कांग्रेस नेतृत्व इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है, जिससे विकास और राजनीति के बीच एक नई बहस खड़ी हो गई है। करीब 90 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली ग्रेट निकोबार परियोजना में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आधुनिक टाउनशिप और ऊर्जा अवसंरचना का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका भू-राजनीतिक महत्व है।

इस योजना की आलोचना करनेवालों को यह भी ध्यान रखना चाहए कि ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के बेहद निकट स्थित है, जहां से विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। वर्तमान में भारत को अपने अधिकांश कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर, कोलंबो और अन्य विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह परियोजना भारत को इस निर्भरता से बाहर निकालने और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान कर सकती है।

राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि परियोजना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी और कुछ बड़े कारोबारी हितों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। राहुल गांधी ने इसे 卐ग्रीन बनाम ग्रीड卐 की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, किंतु इन आरोपों के बीच यह प्रश्न भी उठता है कि यदि परियोजना का उद्देश्य सिर्फ निजी लाभ होता, तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार, बंदरगाह विकास, हवाई संपर्क और ऊर्जा अवसंरचना जैसे व्यापक आयाम क्यों शामिल किए जाते?

यह सच है कि आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, पर क्या इस का अर्थ यह माना जाए कि आलोचना तथ्यों के आधार पर न होकर सिर्फ कल्पना या जो मन में आ गया अथवा सत्ता पक्ष पर आरोप ही लगाना है, इसलिए कुछ भी बोल दिया जाएगा? आरोप लगा दो, बाद में सामने वाला अपनी सफाई देता रहे! वह भी आरोप सिर्फ राजनीतिक धारणा पर केंद्रित होकर लगा दिए जाएं, यह कहां तक सही है?

कांग्रेस का कहना है कि परियोजना से बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र प्रभावित होगा और जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। यह चिंता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। किसी भी विकास परियोजना में पर्यावरणीय प्रभावों का गंभीर मूल्यांकन आवश्यक होता है। यहां कांग्रेस स्वयं यह भूल रही है या देखना ही नहीं चाहती कि इस परियोजना से जुड़ा तथ्य यह है कि इसे भी विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है।

विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा अध्ययन किए गए हैं और अनेक पर्यावरणीय शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है।

सरकार का दावा है कि सीमित क्षेत्र का उपयोग होगा, क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा और संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षित रखा जाएगा। सरकार तो केंद्र में पहले कांग्रेस की भी रही है, उसने भी कई परियोजनाओं पर काम किया, आज के तर्कों के आधार पर तो कांग्रेस के लिए फिर यही कहा जाएगा कि उसे भी वह सब कुछ नहीं करना चाहिए था, जिसे वह कभी भारत के विकास के लिए आवश्यक मानती रही है, इसलिए वास्तविक बहस का विषय यह होना चाहिए कि इन शर्तों का कठोरता से पालन कैसे सुनिश्चित किया जाए, न कि परियोजना को रोक दिया जाए।

कांग्रेस का एक प्रमुख तर्क शोंपेन और निकोबारी जनजातियों के अधिकारों को लेकर है। निश्चित रूप से आदिवासी समुदायों की संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली की रक्षा राष्ट्रीय दायित्व है, किंतु आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार किसी भी जनजातीय समुदाय के व्यापक विस्थापन का प्रस्ताव नहीं है। निगरानी तंत्र, जनजातीय कल्याण उपाय और संरक्षित क्षेत्रों की व्यवस्था भी की गई है। यदि कहीं कमियां हैं, तो उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन पूरी परियोजना को जनजातीय हितों के खिलाफ बताना वास्तविक मुद्दों की गंभीरता को कमजोर कर सकता है।

कांग्रेस यह समझे कि हाल ही में अंडमान-निकोबार क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिलने की खबर ने इस पूरे क्षेत्र के महत्व को और बढ़ा दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी भी साझा की है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को अंडमान अपतटीय बेसिन में श्री विजय पुरम-3 क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की महत्वपूर्ण उपस्थिति मिली है।

यह खोज निश्चित ही ऊर्जा संसाधन के रूप में आज भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में गैस भंडार मिलने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में पूरा अंडमान बेसिन भविष्य में भारत के लिए ऊर्जा क्रांति का केंद्र बन सकता है। नई खोजों से यह सुनिश्चित है कि यह ग्रेट निकोबार परियोजना बंदरगाह और हवाई अड्डे तक सीमित नहीं रह जाती, यह संभावित ऊर्जा हब के रूप में भी उभरती है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और ऊर्जा रणनीति के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित होता है।

लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि बेहतर विकल्प और रचनात्मक सुझाव देना भी होता है। पर्यावरणीय मंजूरियों, पारदर्शिता और स्थानीय समुदायों के हितों पर सवाल उठाना आवश्यक है, लेकिन जब लगभग हर बड़ी राष्ट्रीय परियोजना विरोध का विषय बन जाए, तब जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उद्देश्य सुधार है या अवरोध! वस्तुतः कांग्रेस को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि यदि ग्रेट निकोबार जैसी परियोजनाओं का विरोध किया जाता है, तो भारत अपनी समुद्री, व्यापारिक और ऊर्जा क्षमताओं का विस्तार किस वैकल्पिक मॉडल के माध्यम से करेगा।

न्यायालय के आलोक में बेटी का अधिकार

-डॉ. निवेदिता शर्मा

भारतीय न्यायपालिका ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि न्याय हमेशा समाज की बदलती वास्तविकताओं को स्वीकार करते हुए समानता, गरिमा और मानवीय अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया हालिया निर्णय, जिसमें विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति एवं आश्रित कोटे के लाभों से बाहर रखने को असंवैधानिक ठहराया गया है, भारतीय न्यायिक इतिहास में महिला अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय कहलाएगा ।

वास्तव में यह निर्णय उस सोच को भी चुनौती देता है जो विवाह के बाद बेटी को उसके माता-पिता के परिवार से अलग मान लेने की प्रवृत्ति रखती है। कई बार माता-पिता के लिए भी और कई बार परिवार के भाई एवं अन्य कुटुम्बजनों के लिए। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने स्पष्ट कहा कि विवाहित पुत्री को परिवार की परिभाषा से बाहर रखना मनमाना, अनुचित तथा संविधान के समानता सिद्धांत के विपरीत है।

आज न्यायालय की इस संबंध में अत्यंत सारगर्भित टिप्पणी बता रही है कि विवाह न तो बेटी और उसके माता-पिता के बीच के संबंध को समाप्त करता है और न ही यह मान लेने का कोई आधार देता है कि वह अब अपने परिवार पर आश्रित नहीं रही। इसके साथ ही यह कथन भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त भी करता है, जहां आज असंख्य विवाहित बेटियां अपने माता-पिता की देखभाल करती हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक संबल का आधार बनती हैं तथा कठिन परिस्थितियों में परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती हैं।

आप यह भी कह सकते हैं कि कुलसुम निशा के मामले में न्यायालय ने कानून की व्याख्या नवीन अर्थों के साथ की है, जिसमें जीवन की वास्तविकताओं को महत्व दिया गया। याचिकाकर्ता अपनी माता के निधन के पश्चात अपनी बहनों, जिनमें एक दृष्टिबाधित बहन भी शामिल है, के भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभा रही है। वे अपनी माता के साथ रहती थीं और उचित मूल्य की दुकान के संचालन में सहयोग करती थीं। इसके बावजूद, इसलिए उनकी अर्जी अस्वीकार कर दी गई थी क्योंकि वे विवाहित थीं। अब न्यायालय ने इस आधार को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

यह निर्णय बताता है कि न्यायपालिका व्यक्ति की वास्तविक परिस्थितियों को प्राथमिकता देती है, न कि रूढ़िगत धारणाओं को। वास्तव में यह निर्णय भारतीय संविधान की मूल भावना का विस्तार है। संविधान के अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। यदि विवाहित पुत्र को परिवार का सदस्य माना जा सकता है तो विवाह के कारण विवाहित पुत्री को उस अधिकार से वंचित करना स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभाव ही है। उच्चतम न्यायालय ने इसी असमानता को समाप्त करते हुए एक बार फिर यह संदेश दिया है कि अधिकार व्यक्ति की योग्यता, आवश्यकता और वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्धारित होंगे, न कि उसके लिंग या वैवाहिक स्थिति के आधार पर।

अब यदि हम भारतीय संदर्भ में इस निर्णय को देखें तो ध्यान में आता है कि यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। भारतीय न्यायपालिका का अतीत महिलाओं और बेटियों के अधिकारों को निरंतर सुदृढ़ करने वाले निर्णयों से भरा हुआ है। वर्ष 2020 में उच्चतम न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि पुत्री जन्म से ही पैतृक संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार रखती है। इस निर्णय ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की प्रगतिशील व्याख्या की। साथ में यह भी स्थापित किया कि बेटी परिवार की समान उत्तराधिकारी है, कोई गौण सदस्य नहीं।

इससे पूर्व भी विभिन्न मामलों में न्यायालय ने महिलाओं के संपत्ति अधिकार, गरिमामय जीवन, कार्यस्थल पर सुरक्षा और समान अवसरों को संविधान की मूल भावना के अनुरूप सुदृढ़ किया है। हम यहां यदि भारतीय न्याय परंपरा के व्यापक इतिहास को देखें तो यह कहना अनुचित होगा कि यहां स्त्री या पुत्री के प्रति न्याय का अभाव रहा है। भारतीय संस्कृति और न्याय-दर्शन में नारी को सम्मान का केंद्र माना गया है। मनुस्मृति का प्रसिद्ध वचन भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इसका आशय यह है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहीं समृद्धि, सद्भाव और श्रेष्ठता का वास होता है। यद्यपि समय के साथ सामाजिक व्यवहार में अनेक विकृतियां आईं और कुछ परंपराओं का दुरुपयोग भी हुआ, किंतु भारतीय न्याय-दर्शन का मूल स्वर सदैव नारी सम्मान और संरक्षण के पक्ष में रहा है।

याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति तथा अन्य प्राचीन विधि-ग्रंथों में स्त्रीधन और महिलाओं के अधिकारों को मान्यता दी गई है। भारतीय सभ्यता में माता को सर्वोच्च सम्मान दिया गया, कन्या को पूजनीय माना गया और परिवार व्यवस्था में महिला की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया गया। आधुनिक भारत का संविधान इसी सांस्कृतिक आधार को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाता है, इसलिए जब उच्चतम न्यायालय बेटियों के अधिकारों की रक्षा करता है, तब वह सिर्फ आधुनिक संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं करता बल्कि भारतीय न्याय परंपरा के उस श्रेष्ठ पक्ष को भी आगे बढ़ाता है जिसमें व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि मानी गई है।

उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि परिवार का अर्थ रक्त संबंधों की औपचारिक परिभाषा से ऊपर उठकर जिम्मेदारी, स्नेह, सहयोग और पारस्परिक निर्भरता है। आज की सामाजिक परिस्थितियों में यह मान लेना कि विवाह के बाद बेटी का अपने माता-पिता से संबंध समाप्त हो जाता है, वास्तविकता से परे है। अनेक परिवारों में बेटियां ही माता-पिता की सबसे बड़ी शक्ति और सहारा होती हैं इसलिए किसी कल्याणकारी योजना, अनुकंपा नियुक्ति या आश्रित कोटे के लाभ से उन्हें वैवाहिक स्थिति के आधार पर वंचित करना न्याय और समानता दोनों के विरुद्ध है।

यह निर्णय उन लाखों बेटियों के लिए आशा का संदेश है जो अपने परिवारों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं और समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। साथ ही यह प्रशासनिक तंत्र के लिए भी स्पष्ट निर्देश है कि कल्याणकारी योजनाओं का संचालन संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप किया जाए, न कि पुरानी और अप्रासंगिक धारणाओं के आधार पर। वहीं आज भारतीय न्यायपालिका का यह निर्णय इसलिए विशेष प्रशंसा का पात्र है क्योंकि उसने एक व्यापक सामाजिक संदेश दिया है कि बेटी विवाह के बाद भी बेटी ही रहती है; उसका अपने परिवार पर अधिकार, दायित्व और संबंध किसी वैवाहिक बंधन से समाप्त नहीं होते।

निःस्संदेह, उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता, प्रगतिशीलता और न्यायप्रियता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह निर्णय आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में स्मरण किया जाएगा तथा यह संदेश देता रहेगा कि भारत की न्याय व्यवस्था में बेटी कभी पराई नहीं होती, वह सदैव ही अधिकारों और सम्मान की समान भागीदार होती है।

(लेखिका, मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं।)

अंडर-18 महिला एशिया कपः शूटआउट में चीन से हारा भारत, फाइनल का सपना टूटा

एजेंसी

काकामिगाहारा (जापान)। भारतीय अंडर-18 महिला हॉकी टीम का फाइनल में पहुंचने का सपना बेहद रोमांचक मुकाबले में टूट गया। महिला अंडर-18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने चीन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन निर्धारित समय तक मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहने के बाद शूटआउट में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही चीन ने फाइनल में जगह बना ली। भारत की ओर से नौशीन नाज़ ने तीसरे मिनट में और किरण एक्का ने 54वें मिनट में गोल किए। चीन के लिए ली ज़ेयान ने 24वें मिनट और झांग युरोंग ने 48वें मिनट में गोल दागे। भारत ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की। तीसरे ही मिनट में कप्तान स्वीटी कुजूर के बेहतरीन पास पर नौशीन नाज़ ने घेरे के अंदर से दमदार प्रहार कर गेंद को जाल में पहुंचाया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने अवसर बनाए, लेकिन कोई और गोल नहीं हो सका। दूसरे क्वार्टर में चीन को 21वें मिनट में दंड कोना मिला, लेकिन भारतीय गोलरक्षक महक परिहार ने शानदार बचाव किया। हालांकि 24वें मिनट में भारतीय रक्षा पंक्ति की गलती का फायदा उठाकर ली ज़ेयान ने मैदानी गोल कर चीन को बराबरी दिला दी। तीसरे क्वार्टर में चीन ने अधिक समय तक गेंद अपने नियंत्रण में रखी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने मजबूत रक्षण किया। भारत को भी लगातार दंड कोने मिले, मगर टीम बढ़त हासिल नहीं कर सकी।

भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 पुरुष एशिया कप हॉकी के फाइनल में बनाई जगह

एजेंसी

काकामिगाहारा (जापान)। भारतीय अंडर-18 पुरुष हॉकी टीम ने शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में 5-3 से हराकर अंडर-18 पुरुष एशिया कप 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। अंतिम क्वार्टर तक 2-3 से पीछे चल रही भारतीय टीम ने जबरदस्त आक्रामक खेल दिखाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की जीत के नायक आशीष तानी पूर्ति रहे, जिन्होंने चार गोल दागकर मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने 12वें, 49वें, 53वें और 56वें मिनट में गोल किए, जबकि भारत का एक अन्य गोल शाहरुख अली ने 35वें मिनट में किया। पाकिस्तान की ओर से अदील, मुहम्मद फरहान असलम और उजैर अहमद कुरैशी ने गोल किए। मुकाबले की शुरुआत दोनों

टीमों के बीच मिडफील्ड में कड़ी टक्कर के साथ हुई। भारत को 12वें मिनट में पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे आशीष तानी पूर्ति ने गोल में बदलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई।दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने आक्रामक खेल दिखाया और 27वें मिनट में अदील ने फील्ड गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। तीसरे क्वार्टर में भारत ने 35वें मिनट में शाहरुख अली के गोल से फिर बढ़त बनाई, लेकिन पाकिस्तान ने दो मिनट बाद बराबरी कर ली। इसके बाद 42वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर पाकिस्तान ने पहली बार 3-2 की बढ़त हासिल कर ली। अंतिम क्वार्टर में भारतीय टीम ने दमदार वापसी की। लगातार पेनाल्टी कॉर्नर हासिल करने के बाद आशीष तानी पूर्ति ने 49वें मिनट में गोल कर स्कोर 3-3 कर दिया। इसके बाद उन्होंने 53वें मिनट में हैट्रिक पूरी करते हुए भारत को 4-3 से आगे कर दिया।

मैच खत्म होने से चार मिनट पहले भारत को एक और पेनाल्टी कॉर्नर मिला और आशीष ने अपना चौथा गोल करते हुए टीम की बढ़त 5-3 कर दी। भारतीय खिलाड़ियों ने अंतिम मिनटों में संयम बनाए रखा और जीत सुनिश्चित कर ली।

मैच के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच सरदार सिंह ने कहा, 'सबसे पहले मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। पिछले डेढ़-दो महीने में हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज और प्रशिक्षण शिविरों के दौरान लगातार मेहनत की और हर सत्र में टीम ने सुधार दिखाया। इसी का परिणाम है कि हम फाइनल में पहुंचे हैं। हमारा लक्ष्य अच्छा हॉकी खेलना और प्रशिक्षण में सीखी बातों को मैदान पर लागू करना था। '

राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग में मुरादाबाद की अक्षरा ने जीते दो स्वर्ण पदक

एजेंसी

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की 12 वर्षीय खिलाड़ी अक्षरा कुशवाहा ने आर्म रेसलिंग में राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। अक्षरा ने गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 28 मई से 3 जून तक आयोजित राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में यह उपलब्धि हासिल की। खुशहालपुर स्थित पूनम विहार निवासी मुकेश कुशवाहा और सोनी गंगवार की बेटी अक्षरा कुशवाहा सेंट मैरीज स्कूल, बुद्धि विहार में कक्षा सात की छात्रा हैं। अक्षरा ने राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में सब जूनियर वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए दोनों मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उत्तर प्रदेश से कई खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन मुरादाबाद

की अक्षरा दो स्वर्ण पदक जीतने वाली जिले की एकमात्र बालिका खिलाड़ी रहीं। अक्षरा कुशवाहा के माता-पिता ने बेटी की सफलता पर खुशी जताई है। उनका कहना है कि अक्षरा की सफलता ने केवल मुरादाबाद का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

इंग्लैंड की दूसरी पारी 226 रन पर सिमटी, जीत के लिए न्यूजीलैंड को 254 का लक्ष्य

लॉर्ड्स। लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। गेंदबाजों के दबदबे वाले इस टेस्ट न्यूजीलैंड को चौथी पारी में जीत के लिए 254 रन बनाने होंगे। टेस्ट के दूसरे दिन के तीसरे सेशन में इंग्लैंड की दूसरी पारी 226 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिली थी। बेन डकेट और एमिलो गे ने पहले विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की। 52 के स्कोर पर पहले विकेट के रूप में डकेट 33 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए एमिलो और बेथेल के बीच 47 रन की साझेदारी हुई। बेथेल 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रूट और एमिलो के बीच तीसरे विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी हुई। 126 के स्कोर पर एमिलो 57 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। इंग्लैंड की पारी इसके बाद लड़खड़ा गई और 127 के स्कोर पर 3 विकेट और गंवा दिए। 126 पर 3 वाली इंग्लैंड 127 के स्कोर 6 विकेट गंवा बैठी। सातवें विकेट के लिए गस एटकिंसन और विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने 57 रन की अहम साझेदारी की। एटकिंसन 14 रन बनाकर आउट हुए। स्मिथ ने आठवें विकेट के लिए ओली रॉबिन्सन के साथ 29 रन की साझेदारी की। स्मिथ आठवें विकेट के लिए रूप में 213 के स्कोर पर 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद इंग्लैंड की पारी 226 रन पर सिमट गई। रॉबिन्सन आखिरी विकेट के रूप में 29 रन बनाकर आउट हुए।

डीडीसीए महिला टी-20 लीग के दूसरे संस्करण का आगाज़, 60 टीमें और 700 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड में डीडीसीए महिला टी-20 लीग 2026 के दूसरे संस्करण का औपचारिक शुभारंभ किया। राजधानी की इस प्रमुख महिला क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता में इस बार रिकॉर्ड भागीदारी देखने को मिलेगी।

टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण में टीमों की संख्या 42 से बढ़कर 60 हो गई है, जबकि 700 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगी। मुकाबले दिल्ली के विभिन्न मैदानों पर खेले जाएंगे। डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने उद्घाटन अवसर पर कहा कि महिला क्रिकेटरों के लिए पूरे वर्ष अवसर उपलब्ध कराना और क्लब स्तर से आगे बढ़ने का मजबूत रास्ता तैयार करना संघ की प्राथमिकता है।

डीडीसीए उपाध्यक्ष शिखा कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या दिल्ली में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता का संकेत है। वहीं सचिव अशोक शर्मा ने

क्लबों के सहयोग को प्रतियोगिता की सफलता का आधार बताया। डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा ने कहा कि दिल्ली के क्रिकेट क्लब हमेशा संघ की संरचना की रीढ़ रहे हैं और इसी सहयोग की वजह से यह प्रतियोगिता लगातार मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला क्रिकेटरों के लिए अधिक अवसर तैयार करना और प्रतिभा के दायरे का विस्तार करना है।

अंडर-14 क्रिकेट गोल्ड कप : एमपीएस क्रिकेट एकेडमी सात विकेट से जीती

एजेंसी

मुरादाबाद,। मुरादाबाद अंडर-14 क्रिकेट गोल्ड कप के दूसरे मुकाबले में पारकर एकेडमी के मैदान पर एमपीएस क्रिकेट एकेडमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डूमफ्लेयर क्रिकेट एकेडमी को सात विकेट से हरा दिया। मैच में 5 विकेट लेने और बल्ले से 34 रन की उपयोगी पारी खेलने वाले विशुदीप को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए डूमफ्लेयर की पूरी टीम 22.2 ओवर में 97 रन पर सिमट गई। डूमफ्लेयर की ओर से सूर्यकांत ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। उनके अलावा ग्रंथ ने 11, साहिल यादव और रुद्राक्ष ने नौ-नौ रन का योगदान दिया। टीम को अतिरिक्त के रूप में 24 रन मिले, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। एमपीएस की ओर से कप्तान विशुदीप ने घातक गेंदबाजी करते हुए छह ओवर में मात्र नौ रन देकर पांच विकेट झटके। आरुष ने दो, राजस भटनागर और वंश सक्सेना ने एक-एक विकेट हासिल किया।98 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमपीएस क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत अच्छी

नहीं रही और अयान सुधाकर बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद अनंत ने 13 रन और कप्तान विशुदीप ने तेजतर्रार 34 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। विशुदीप ने अपनी पारी में तीन चौके और तीन छक्के लगाए। दिव्यांश यादव ने नाबाद 17 और ए. बनर्जी ने नाबाद 12 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। एमपीएस की जीत में अतिरिक्त रनों की भी अहम भूमिका रही। टीम को 23 रन अतिरिक्त के रूप में मिले। लक्ष्य का पीछा करते हुए एमपीएस ने 14.4 ओवर में तीन विकेट खोकर 99 रन बना लिए और मुकाबला सात विकेट से अपने नाम कर लिया। मैच में पांच विकेट लेने और बल्ले से 34 रन की उपयोगी पारी खेलने वाले विशुदीप को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

त्रिकोणीय सीरीजः तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया 'ए' टीम श्रीलंका पहुंची

दांबुला । श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए टीम के साथ होने वाली वनडे फॉर्मेट की त्रिकोणीय सीरीज के लिए तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारत ए टीम श्रीलंका पहुंच गई। सीरीज 9 से 21 जून तक रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। इंडिया 'ए' अपने अभियान की शुरुआत 9 जून को मेजबान श्रीलंका 'ए' के खिलाफ करेगी। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़ और अनुकूल रॉय जैसे खिलाड़ियों के पहुंचने की तस्वीरें शेयर की हैं। एसएलसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, 'इंडिया 'ए' टीम रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली ट्राई-नेशन सीरीज से पहले श्रीलंका पहुंच गई है। अपनी स्किल्स दिखाने और एक रोमांचक टूर्नामेंट में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एक्शन शुरू होने दें। ' श्रीलंका पहुंचने से पहले इंडिया 'ए' टीम में दो बड़े बदलाव किए गए - हर्ष दुबे को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टेस्ट और वनडे टीमों में शामिल किया गया, जिसके बाद रॉय को टीम में शामिल किया गया।

श्रीलंका के जेवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा ने नीरज चोपड़ा का तोड़ा रिकॉर्ड, 92.62 मीटर दूर फेंका भाला

रोम । श्रीलंका के स्टार जेवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा पथिरगे ने वांडा डायमंड लीग की प्रतिष्ठित गोल्डन गाला पिएत्रो मेनेया प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 92.62 मीटर दूर भाला फेंका और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पथिरगे ने अपने पहले ही प्रयास में 84.49 मीटर का थ्रो किया, जो जीत के लिए काफी माना जा रहा था। हालांकि, इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में 90 मीटर की दूरी को भी पार कर दिया। इसी थ्रो के साथ ही वह साल 2026 सीजन में 90 मीटर या उससे अधिक दूरी का थ्रो फेंकने वाले पहले एथलीट बने। रुमेश ने 92.62 मीटर का थ्रो फेंकते हुए 20 साल से कायम एंड्रियास थोरकिल्डसन के 90.34 मीटर के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। इस ऐतिहासिक थ्रो के साथ वह दुनिया की ऑल-टाइम लिस्ट में आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि वह दूसरा सबसे बेस्ट थ्रो करने वाले एशियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 90.23 मीटर का थ्रो फेंका था। रुमेश का यह थ्रो 2024 ओलंपिक फाइनल के बाद से दुनिया का सबसे लंबा थ्रो भी रहा। इस प्रदर्शन ने उन्हें दो बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स पर स्पष्ट बढ़त दिलाई, जिन्होंने 83.91 मीटर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।

श्रेयस अय्यर बने काबुनी के सुपर कोच, क्रिकेट प्रशिक्षण को मिलेगा तकनीक का साथ

एजेंसी

मुंबई। एआई आधारित स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म काबुनी ने भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर को सुपर कोच के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। कंपनी का मानना है कि श्रेयस अय्यर के जुड़ने से तकनीक और विश्वस्तरीय क्रिकेट अनुभव को एक मंच पर लाने की उसकी पहल को नई गति मिलेगी।

श्रेयस अय्यर अब काबुनी के सुपर कोच समूह का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें पहले से सौरव गांगुली, शेन वॉटसन और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये सभी 7 जून को मुंबई में आयोजित काबुनी शोकेस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान कंपनी अपने प्लेटफॉर्म और उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध अवसरों को प्रस्तुत करेगी।कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में 'वॉन्ट टू प्ले फॉर ए लीजेंड?' नाम का राष्ट्रीय युवा क्रिकेट टूर्नामेंट भी शामिल होगा, जिसकी शुरुआत जून में होगी। इसमें 12 से 16 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले

सकेंगे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी काबुनी की तकनीक आधारित मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और श्रेयस अय्यर की टीम में स्थान पाने का अवसर हासिल करेंगे। काबुनी खिलाड़ियों के प्रदर्शन और गेंद से जुड़े आँकड़ों का वास्तविक समय में विश्लेषण करता है और उन्हें आवाज, वीडियो तथा दृश्य आधारित व्यक्तिगत फीडबैक उपलब्ध कराता है। यह मंच छोटे-छोटे सुधारों के माध्यम से खिलाड़ियों के दीर्घकालिक विकास की अवधारणा पर कार्य करता है। बायोमैकेनिक्स और गति विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों की सहायता से काबुनी ऐसी प्रशिक्षण सुविधाएँ खिलाड़ियों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है, जो पहले केवल उच्च स्तर के क्रिकेटरों तक सीमित मानी जाती थीं।श्रेयस अय्यर ने कहा, 'भारतीय क्रिकेट में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत सही मार्गदर्शन और सटीक फीडबैक की है। खिलाड़ी जहाँ हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच का अंतर बहुत छोटा होता है। काबुनी इस दूरी को कम करने का प्रयास कर रहा है और खिलाड़ियों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए बेहतर साधन दे रहा है। ' काबुनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमेश पटेल ने कहा, 'श्रेयस अय्यर आधुनिक क्रिकेट की नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका दृष्टिकोण हमारे विजन से मेल खाता है। हमारा उद्देश्य ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना है जो तकनीकी रूप से मजबूत होने के साथ मानसिक रूप से भी आत्मविश्वासी हों। '

खराब रोशनी में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल के पक्ष में गंभीर, बोले- नतीजा निकलने का मौका मिलना चाहिए

एजेंसी

न्यू चंडीगढ़। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें खराब रोशनी की स्थिति में टेस्ट मैच के दौरान लाल गेंद की जगह गुलाबी गेंद के इस्तेमाल की बात कही गई है। गंभीर ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि मैच का परिणाम निकालने का मौका बनता है, तो उसे हर हाल में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी टेस्ट निर्णायक हो और खराब रोशनी के कारण पूरा मैच न खेला जा सके, तो यह टीमों के साथ अन्याय होगा।

उन्होंने कहा, 'मैं इस विचार का समर्थन करता हूं। अगर दोनों टीमों के कप्तान सहमत हों और मैच का परिणाम निकल सकता हो, तो ऐसा होना चाहिए। खिलाड़ी दो साल मेहनत करते हैं और अगर खराब रोशनी की वजह से अवसर छिन जाए तो यह उचित नहीं होगा। ' भारतीय टीम हाल ही में घरेलू टेस्ट शृंखला में दक्षिण अफ्रीका से 2-0 से हार चुकी है। फिलहाल भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में नौ मैचों में 48.15 प्रतिशत अंकों के साथ छठे स्थान पर है। इसके बावजूद गंभीर ने फाइनल में पहुंचने को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, 'जब तक आपके पास फाइनल में पहुंचने का मौका है, तब तक उम्मीद बनी रहती है। हमारे पास प्रतिभा और गुणवत्ता दोनों हैं। एक खराब शृंखला से हमारी क्षमता कम नहीं हो जाती। ड्रेसिंग रूम में हर खिलाड़ी मानता है कि हम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकते हैं। ' अफगानिस्तान टेस्ट भले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली टेस्ट शृंखलाओं से पहले यह भारत के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला माना जा रहा है।

विश्व योगासन चैंपियनशिप में भारत की दमदार शुरुआत, पहले दिन जीते पांच स्वर्ण पदक

एजेंसी

अहमदाबाद। मेजबान भारत ने पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले दिन दांव पर लगे छह में से पांच स्वर्ण पदक जीतकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। एका एरिना में आयोजित इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआती मुकाबलों से ही दबदबा कायम रखा। पश्चिम बंगाल के अभय बर्मन और रितु मंडल ने पारंपरिक योगासन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के स्वर्णिम अभियान की शुरुआत की। सीनियर पुरुष वर्ग में अभय बर्मन ने 63.42 अंक हासिल कर विश्व योगासन चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण भारत के नाम किया। इंडोनेशिया के अर्कान रियांतो 57.23 अंकों के साथ रजत और उज्बेकिस्तान के एलन 53.21 अंकों के साथ कांस्य पदक विजेता बने। अपनी उपलब्धि पर अभय बर्मन ने कहा, 'विश्व योगासन चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण भारत के लिए जीतना मेरे जीवन का यादगार पल है। घरेलू दर्शकों के सामने खेलना मेरे लिए अतिरिक्त प्रेरणा लेकर आया। ' इसके बाद सीनियर महिला वर्ग में रितु मंडल ने 64.33 अंक लेकर भारत को दूसरा स्वर्ण दिलाया। कजाखस्तान की ऐझान कुआनिशबायेवा ने रजत और हांगकांग की लैम न्गा मान ने कांस्य पदक जीता। रितु मंडल ने कहा, 'यह प्रतियोगिता योगासन खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक अवसर है। 12 वर्ष की उम्र से शुरू किए गए सफर के बाद 20 वर्ष की उम्र में भारत के लिए पदक जीतना बेहद खास है। ' भारत को एकमात्र झटका सीनियर ए पुरुष वर्ग में लगा, जहां सिंगापुर के नाथानियल टैन लियोंग आन ने 55.37 अंकों के साथ स्वर्ण जीतकर भारतीय क्लीन स्वीप रोक दी। तंजानिया के करिमु स्वाफी को रजत मिला जबकि भारत के सुमिर ग्नावली ने कांस्य पदक जीता।हालांकि भारत ने तुरंत वापसी की और सीनियर ए महिला वर्ग में रितु ठाकुर ने 63.50 अंक लेकर स्वर्ण अपने नाम किया। अर्जेंटीना की नबिला सोल बर्राजा दूसरे और केन्या की अवोर साउलिन्हा तीसरे स्थान पर रहीं। सीनियर बी पुरुष वर्ग में रोशन थापा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 65.67 अंक हासिल किए और भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। बांग्लादेश के मोहम्मद मामून खान बाबू को रजत तथा किर्गिस्तान के दानिल रिकोव को कांस्य पदक मिला। दिन का समापन भारत की ज्योति देउरकर ने ट्विस्टिंग बॉडी व्यक्तिगत सीनियर बी महिला वर्ग में स्वर्ण जीतकर किया। उन्होंने 46.14 अंक प्राप्त किए। ओमान की ओलिमुथु नवामणि को रजत और जापान की साओरी क्युएई को कांस्य मिला। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 योगासन को वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

डिस्ट्रिक्ट इंटर क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट : रुक्मणी एकेडमी रेड ने रुक्मणी ब्लू को 3 विकेट से हराया

एजेंसी

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट इंटर क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट में रुक्मणी क्रिकेट एकेडमी के मैदान पर खेले गए एक लीग मैच में रुक्मणी एकेडमी रेड ने रुक्मणी एकेडमी ब्लू टीम को तीन विकेट से हराया। मैच में सबसे ज्यादा रन अतिरिक्त के रूप में मिले। जिनकी बदौलत दोनों टीमों का स्कोर आगे बढ़ा। विजेता टीम को कुल 52 अतिरिक्त रन मिले।

डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुरादाबाद के सचिव व पूर्व रणजी खिलाडी विजय गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि पहले बल्लेबाजी करते हुए रुक्मणी एकेडमी ब्लू टीम 34.5 ओवर में 119 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से यश ने सबसे अधिक 28 रन बनाए, जबकि अलमाज ने 20 और मो. उवैस ने पांच रन का योगदान दिया। बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना

सके और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। टीम के कुल 119 रन में 50 रन अतिरिक्त के रूप में मिले। रुक्मणी एकेडमी रेड की ओर से गेंदबाजी में मो. हुसैन और मो. असद ने दो-दो विकेट झटके। कप्तान आयुष कुमार ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 4.5 ओवर में मात्र छह रन देकर दो विकेट हासिल किए। अब्दुल शामी ने एक विकेट लिया। 120 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रुक्मणी एकेडमी रेड का पहला विकेट महज दो रन पर गिर गया। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज सुफियान ने 22 रन, मो. जीशान ने 23 रन और मो. हुसैन ने 15 रन बनाकर टीम को संभाला।हालांकि बीच-बीच में विकेट गिरते रहे, लेकिन बल्लेबाजों ने आवश्यक रन गति बनाए रखी। इस पारी में भी अतिरिक्त रन निर्णायक साबित हुए। विजेता टीम को कुल 52 अतिरिक्त रन मिले, जिनमें 45 वाइड शामिल थीं। आखिरकार टीम ने 19.4 ओवर में 120 रन बनाकर सात विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

फीफा विश्व कप टिकटिंग में तकनीकी खामी, फैंस ने बिना भुगतान के खरीद लिए टिकट

एजेंसी

नई दिल्ली । फीफा को फीफा वर्ल्ड कप 2026 की टिकट बिक्री के दौरान एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। फुटबॉल फैंस ने बिना भुगतान किए विश्व कप के टिकट खरीद लिए। इससे फीफा को नुकसान हुआ। फुटबॉल की वैश्विक संस्था ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बिना भुगतान के खरीदे गए टिकटों को रद्द कर दिया है और फैंस से कीमत अदा करने की अपील की है। फीफा के मुताबिक, 'लगभग 60 प्रशंसकों को 3 जून को एक आधिकारिक संदेश भेजा गया, जिसमें बताया गया कि चेकआउट प्रक्रिया के दौरान हुई भुगतान संबंधी समस्या के कारण उन्हें टिकट बिना किसी भुगतान शुल्क के आवंटित हो गए थे। यह एक तकनीकी त्रुटि थी और टिकटों की वास्तविक कीमत सिस्टम में सही ढंग से प्रदर्शित नहीं हो सकी। प्रशंसकों द्वारा खरीदे गए टिकट सुरक्षित रखे जाएंगे और उन्हें सही राशि का भुगतान करने के लिए आमंत्रित किया गया है।' मामले से जुड़ा एक कथित ई-मेल भी सामने आया है, जिसे टिकट टॉक नेटवर्क ने ऑनलाइन साझा किया। ई-मेल के अनुसार, फीफा ने टिकटों की कीमत में आई गड़बड़ी की पहचान कर उसे ठीक कर दिया है। संगठन ने बताया कि 21 मई 2026 को फीफा की आधिकारिक टिकटिंग वेबसाइट पर हुई इस समस्या के कारण कुछ टिकट चेकआउट के समय गलत कीमत पर दिखाई दिए और उसी आधार पर लेनदेन भी पूरा हो गया।

साई और त्सुकुबा विश्वविद्यालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, खेल विज्ञान और उच्च प्रदर्शन खेलों को मिलेगा बढ़ावा

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत के खेल प्रदर्शन तंत्र को मजबूत बनाने और आगामी बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की तैयारियों को गति देने की दिशा में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और जापान के प्रतिष्ठित त्सुकुबा विश्वविद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

यह साझेदारी खेल शिक्षा, खेल विज्ञान और खिलाड़ियों के विकास के क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग को नई दिशा देगी। यह समझौता तीन वर्षों के लिए किया गया है और वर्ष 2016 में भारत-जापान सरकारों के बीच बने खेल सहयोग ढांचे तथा वर्ष 2018 में साई और त्सुकुबा विश्वविद्यालय के बीच हुए संस्थागत समझौते को आगे बढ़ाता है। समझौते पर त्सुकुबा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर क्योसुके नागाटा और भारतीय खेल प्राधिकरण की उप महानिदेशक मंजुश्री दयानंद ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष ओसामु ओनेदा ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में खेल प्रतिभाओं का विकास, खेलों की सतत प्रगति, कोच विकास और उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए नए ढांचे तैयार करना है। उन्होंने कहा, 'खेल शिक्षा और खेल विज्ञान किसी भी खेल तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यह सहयोग भारत और जापान के बीच खेल गतिविधियों को और बेहतर दिशा देगा। ' यह नया समझौता ऐसे समय हुआ है जब भारत वर्ष 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी और वर्ष 2036 ओलंपिक की दावेदारी को ध्यान में रखते हुए अपने खेल ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रहा है। साई की उप महानिदेशक मंजुश्री दयानंद ने कहा, 'इस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय सहयोग केवल खिलाड़ियों की तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कोच, खेल वैज्ञानिक, प्रशासक और सहयोगी स्टाफ की क्षमता भी बढ़ेगी। भारत बड़े आयोजनों की तैयारी कर रहा है और ऐसे समय में यह समझौता खेल विज्ञान और खेल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। ' समझौते के तहत दोनों संस्थान खेल शिक्षा, ओलंपिक एवं पैरालंपिक शिक्षा, पाठ्यक्रम विकास, कोच शिक्षा, खेल प्रबंधन, खेल अवसंरचना विकास, खेल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, शक्ति एवं कंडीशनिंग, चोट रोकथाम, खेल विज्ञान अनुसंधान और खिलाड़ियों के प्रदर्शन सुधार जैसे क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों, कोचों, खेल वैज्ञानिकों और साई अधिकारियों को जापान में विशेष प्रशिक्षण, आदान-प्रदान कार्यक्रम और अध्ययन के अवसर मिलेंगे। यह सहयोग विशेष रूप से एथलेटिक्स, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, तैराकी और जूडो जैसे खेलों पर केंद्रित रहेगा, जिनमें भारत आने वाले वर्षों में अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत करना चाहता है। इस साझेदारी के तहत खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, प्रदर्शन विश्लेषण और शोध परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही त्सुकुबा इंटरनेशनल अकादमी फॉर स्पोर्ट स्टडीज के माध्यम से इंटर्नशिप और शैक्षणिक अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण और त्सुकुबा विश्वविद्यालय के बीच यह समझौता खेल विज्ञान, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धति और खिलाड़ी प्रबंधन से जुड़े वैश्विक अनुभव भारत तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और दीर्घकाल में भारतीय खेलों को नई मजबूती प्रदान करेगा।

भारत-ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला का शुभारंभ किया

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और यूनाइटेड किंगडम की विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों की राज्य सचिव यवेट कूपर ने नई दिल्ली में गुरुवार को महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला (जीएससीओ) का औपचारिक शुभारंभ किया। खान मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जीएससीओ का शुभारंभ महत्वपूर्ण खनिजों और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर भारत और ब्रिटेन की बढ़ती साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने में सहयोग को मजबूती मिली है। इस पहल से महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत-ब्रिटेन सहयोग मजबूत होगा। मंत्रालय ने कहा कि यह वेधशाला 'टेक्समिन' (टीटीआरपी, डीएसटी, भारत सरकार), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी और विश्लेषण के लिए एक डेटा-संचालित मंच बनाना है।

दिसंबर तक 75 लाख घरों की छतों पर लग जाएगी सौर प्रणाली: प्रल्हाद जोशी

नई दिल्ली। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को विश्वास जताया कि 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत दिसंबर तक 75 लाख घरों में छतों पर सौर इकाई (रूफटॉप सोलर) लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि प्रह्लाद जोशी ने यहां आयोजित 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दो साल: 1 करोड़ छतों तक सोलर होम का विस्तार' कार्यक्रम के दौरान एक बातचीत में हिस्सा लेते हुए यह बात कही। इस अवसर पर प्रह्लाद जोशी ने 'पीएम सूर्य घर' का लोगो और व्हाट्सएप बॉट लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 2 साल के भीतर ही 40 लाख घरों का आंकड़ा पार कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर 2026 तक हम 75 लाख घरों का आंकड़ा भी पार कर लेंगे। फिलहाल इस योजना के तहत करीब 41 लाख घरों में सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता तेज़ी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पहले 50 गीगावॉट तक पहुंचने में 96 महीने लगे। इसके बाद अगले 50 गीगावॉट के लिए 36 महीने लगे और 100 गीगावॉट से 150 गीगावॉट तक पहुंचने में केवल 14 महीने लगे।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सकारात्मक रही वार्ता : वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जो दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों की एक से चार जून तक चली बातचीत के समापन के बाद यह बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच चार दिनों की बातचीत के बाद भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय आंतरिक व्यापार समझौते (बीटीए) पर चर्चा करने के हेतु अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का 1 से 4 जून, 2026 तक दिल्ली का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने वस्तुओं के व्यापार, गैर-शुल्कीय उपायों, सीमा शुल्क एवं व्यापार सुगमीकरण, आर्थिक सुरक्षा समन्वय तथा अन्य पारस्परिक हितों के क्षेत्रों सहित विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की।

सीतारमण ने महिला संचालित मूंगफली प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के यादगीर जिले में महिलाओं के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) समर्थित मूंगफली प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। यह ऐसी इकाई है, जो मूंगफली को भून सकती है, तेल निकाल सकती है और पीनट बटर जैसे उत्पाद बना सकती है। सीतारमण ने बाडेपल्ली गांव में किसानों के प्रशिक्षण और साझा सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कर्नाटक के यादगिर स्थित बडेपल्ली गांव में 'किसान प्रशिक्षण एवं साझा सुविधा केंद्र' के उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में पेड्डापल्ली महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड की सराहना की, जो इस इकाई का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में स्थापित ऐसी सात मूल्य संवर्धन इकाइयों में से यादगीर की इकाई अकेली है, जिसे पूरी तरह महिलाएं चला रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इस इकाई का संचालन करने वाली महिलाओं को किसानों से सीधे मूंगफली खरीदने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं मंडियों एवं बाजारों से खरीद करने की कोशिश कर रही हैं और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने इसके लिए अलग से एक अधिकारी भी नियुक्त किया है। फिर भी ऐसा लगता है कि बीच में कोई बिचौलिया उन्हें सीधे खरीदने से रोक रहा है।

भारत की विकास रफ्तार तेज, यात्री वाहन बिक्री में जोरदार उछाल: पीयूष गोयल

एजेंसी

नई दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की विकास यात्रा पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उन्होंने देश के यात्री वाहन बाजार के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि मई 2026 में इस क्षेत्र में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मई 2026 में भारत के यात्री वाहन बाजार में लगभग 4.4 लाख वाहनों की बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि में प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों - मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा - की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पीयूष गोयल ने कहा, 'भारत की विकास रफ्तार पूरी रफ्तार में है। मई 2026 में देश के यात्री वाहन बाजार में करीब 4.4 लाख यूनिट की बिक्री हुई,

जो सालाना आधार पर 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। यह बढ़त मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स और महिंद्रा ऑटो के नेतृत्व में हुई है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। '

उन्होंने कहा कि भारत में बने वाहनों की बढ़ती मांग घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास और देश के मजबूत ऑटोमोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है।

मंत्री ने कहा, 'मेक इन इंडिया वाहनों की मजबूत मांग उपभोक्ताओं के बढ़ते भरोसे, फलते-फूलते विनिर्माण तंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन के परिवर्तनकारी प्रभाव को दिखाती है। '

पीयूष गोयल ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र की इस प्रगति को देश में चल रहे व्यापक आर्थिक बदलाव से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' पहल ने विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र की यह गति नवाचार, उद्यमशीलता और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाती है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान दे रही हैं।

मंत्री ने कहा, 'विकसित भारत की यात्रा नवाचार, उद्यमशीलता और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से संचालित हो रही है। '

इस महीने की शुरुआत में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने मई में घरेलू बाजार में अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की थी। कंपनी ने मई में डीलरों को 1,90,337 यात्री वाहन भेजे। उद्योग के अनुमान के अनुसार, यह पिछले वर्ष की तुलना में 39.99 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके साथ ही, कंपनी ने अप्रैल में बनाए गए 1,87,704 यूनिट के अपने पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।

विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड से होने वाली कमाई अब होगी टैक्स-फ्री

एजेंसी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों की भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय और मुनाफ़े पर सभी तरह के टैक्स हटा दिए हैं। इस कदम का मकसद देश के सॉवरेन डेट मार्केट को ग्लोबल कैपिटल के लिए ज्यादा आकर्षक बनाना है। ये बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से से लागू होंगे। केंद्र सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में किए गए निवेश पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को समाप्त करने का फैसला किया है। मंत्रालय के मुताबिक इस संबंध में एक अध्यादेश भी जारी किया गया है। इसका मकसद देश में डॉलर के प्रवाह को बढ़ाना है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) को सरकारी सिक्योरिटीज (जी-सेक) से होने वाली ब्याज कमाई और कैपिटल गेंस (मुनाफे) पर टैक्स से पूरी छूट दे दी है। इसके लिए भारत सरकार 'आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026' लेकर आई है, जिसे 5 जून को जारी किया गया। यह फैसला 1 अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में घोषणा की कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (पीआरओआई) को 'पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम' के जरिए सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के शेयर प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यह स्कीम पहले सिर्फ एनआआई/ओसीआई के लिए उपलब्ध थी। मंत्रालय के मुताबिक इस अध्यादेश के जरिये आयकर अधिनियम में संशोधन कर यह छूट प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने दीर्घकालिक एवं स्थिर पूंजी आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर हटाने का फैसला किया है।

आरबीआई के फैसलों के बाद आ सकता है 40 अरब डॉलर तक का कैपिटल इनफ्लो - एसबीआई रिपोर्ट

एजेंसी

नई दिल्ली। एसबीआई रिसर्च की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी (आरबीआई -एमपीसी) द्वारा लिए गए फैसलों से देश में 40 अरब डॉलर का कैपिटल इनफ्लो देखने को मिल सकता है और इससे डॉलर के मुकाबले रुपया 92-93 के स्तर पर जा सकता है। साथ ही कहा कि केंद्रीय बैंक अगस्त की मौद्रिक नीति में भी ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है। रिपोर्ट में एसबीआई रिसर्च ने कहा, 'हमारा मानना ??है कि आरबीआई ब्याज दरों में संभावित वृद्धि पर विचार करने से पहले महंगाई के आंकड़ों का विश्लेषण करना जारी रखेगा। बाजार की उम्मीदों के विपरीत, विकास संबंधी कारक ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि के चक्र को दरकिनार कर सकते हैं। हमें अगस्त में नीतिगत दरों में कोई बदलाव न होने की उम्मीद है। '

एसबीआई रिसर्च ने कहा कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और तटस्थ रुख जारी रखने का निर्णय लिया, जबकि विकास अनुमानों को 30 बीएसपी समायोजित करके 6.6 शांति और आत्मविश्वास का संकेत देता है और निराशावादी धारणाओं को रोकता है जो संभावित रूप से रुपए पर सट्टेबाजी को जन्म दे सकती हैं। '

प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही, सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान को भी 50 बीएसपी संशोधित करके अब 5.1 प्रतिशत कर दिया है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया , 'गहन विश्लेषण के आधार पर, हमें लगता है कि मौद्रिक नीति की भाषा मुद्रास्फीति पर निगरानी और बाहरी क्षेत्र से बचाव पर केंद्रित रही है, हालांकि नीति का रुख तटस्थ है। यह विवेकपूर्ण कदम है क्योंकि यह आरबीआई की ओर से

एसबीआई रिसर्च ने बताया कि आरबीआई ने नीति वक्तव्य में एक बार फिर स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि कभी-कभी रुपए की चाल मूलभूत कारकों के अनुरूप नहीं होती है। रिपोर्ट में कहा गया, 'इससे उन हालिया अनावश्यक आरोपों पर विराम लग जाता है कि रुपए को 100 तक भी बढ़ने दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अनावश्यक दावे रुपए पर सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। '

देश के तेज आर्थिक विकास के लिए मोदी सरकार सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

एजेंसी

नई दिल्ली। वैश्विक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार देश की तेज आर्थिक वृद्धि के लिए 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से दिया गया। वित्त मंत्रालय की ओर से यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश की जीडीपी वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही है और इस दौरान रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च अवधि) में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत और जीवीए वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रही।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'विशेष रूप से, विनिर्माण, व्यापार, मरम्मत, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, भंडारण और वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2025-26 में स्थिर और वर्तमान दोनों कीमतों पर दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल की है। ' आर्थिक बुनियाद आलोचकों की कल्पना से कहीं अधिक मजबूत साबित हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, 'जिन लोगों ने महीनों तक भारत में आर्थिक मंदी की

सरकारी डेटा के मुताबिक, बीते वित्त वर्ष में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का प्रदर्शन मजबूत रहा है। इनकी वृद्धि दर स्थिर कीमतों में क्रमशः 8.8 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत रही है।

दूसरी तरफ, वित्त वर्ष 26 में उच्च विकास दर रहने पर बीजेपी नेता डॉ. सैयद जफर इस्लाम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी भविष्यवाणी की थी, उनके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहले 7.1 प्रतिशत थी। यह ईरान संघर्ष, टैरिफ युद्ध और वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संभव हुआ है। एक बार फिर, हमारी आर्थिक बुनियाद आलोचकों की कल्पना से कहीं अधिक मजबूत साबित हुई है। '

अंडमान के अपतटीय ब्लॉक में ऑयल इंडिया ने की प्राकृतिक गैस की नई खोज, तीसरे खोजी कुएं में हाइड्रोकार्बन की पुष्टि

एजेंसी

नई दिल्ली । सरकारी महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान के उथले समुद्री (अपतटीय) ब्लॉक में अपने तीसरे खोजी कुएं में प्राकृतिक गैस की नई खोज की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी का एक और महत्वपूर्ण संकेत है। कंपनी के अनुसार, विजयपुरम-3 (स्थान ओएईबी) नामक यह कुआं ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) के तहत ऑफशोर अंडमान ब्लॉक एएन-ओएसएचपी-2018/1 में ड्रिल किया गया है। यह कुआं अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है, जहां पानी की गहराई 355 मीटर है। कंपनी ने बताया कि ड्रिलिंग कार्य इयोसीन भू-स्तर में 1,900 मीटर से अधिक गहराई तक किया गया। एक्सचेंज फाइलिंग में ऑयल इंडिया ने बताया कि कुएं के प्रारंभिक उत्पादन परीक्षण में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। छिद्रण (परफोरेशन) के बाद लगातार गैस जलती हुई दिखाई दी, जो गैस की उपलब्धता का संकेत है। कंपनी ने बताया कि कुएं में दबाव तेजी से

बढ़ा और इसके बाद गैस का उत्पादन शुरू हो गया। ऑयल इंडिया ने अपनी नियामकीय फाइलिंग में कहा, 'ऑयल इंडिया लिमिटेड को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत ऑफशोर अंडमान ब्लॉक एएन-ओएसएचपी-2018/1 में अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से 15 किलोमीटर दूर और 355 मीटर जल गहराई पर ड्रिल किए गए तीसरे खोजी कुएं विजयपुरम-3 (स्थान ओएईबी) में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी मिली है। 'कंपनी ने कहा कि फिलहाल गैस के नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है ताकि उसकी संरचना और ऊष्मीय क्षमता (कैलोरिफिक वैल्यू) का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही समस्थानिक (आइसोटोप) अध्ययन भी किया जा रहा है, जिससे हाइड्रोकार्बन के स्रोत और उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी। यह अंडमान अपतटीय ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन की दूसरी पुष्टि है। इससे पहले सितंबर 2025 में दूसरे खोजी कुएं विजयपुरम-2 (स्थान ओएईए) में भी प्राकृतिक गैस की खोज हुई थी।

अब तक इस ब्लॉक में तीन खोजी कुएं ड्रिल किए जा चुके हैं, जिनमें से दो में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। कंपनी ने इस नई खोज को एक महत्वपूर्ण संकेतक बताया है, जो इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के स्रोत, उनके प्रवाह मार्ग या संभावित भंडार की मौजूदगी की ओर इशारा करता है। ऑयल इंडिया का मानना है कि यह खोज भविष्य में क्षेत्र में होने वाली खोज और उत्पादन गतिविधियों की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अनुमान से ज्यादा रही 2025-26 की जीडीपी, 7.7 फीसदी की दर से बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था

एजेंसी

नई दिल्ली । देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने नई दिल्ली में नए आंकड़े पेश करके कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7 फीसदी की दर से जीडीपी बढ़ी है, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 7.1 फीसदी के मुकाबले ज्यादा है।

सीईए वी. अनंत नागेश्वरन ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की (जनवरी-मार्च) चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ 7.8 फीसदी रही है। उन्होंने बताया कि इस तिमाही के दमदार प्रदर्शन की वजह से पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की आर्थिक विकास दर 7.7 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.8 फीसदी रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि स्थिर कीमतों पर जीडीपी का आकार वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 323.12 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के पहले संशोधित अनुमान 299.89 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। वहीं, मौजूदा कीमतों पर जीडीपी का आकार वित्त वर्ष 2025-26 में 346.36 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 318.07 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 8.9 फीसदी की वृद्धि को दर्शाता है। जीडीपी के आंकड़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों के बीच एक संतुलित तस्वीर पेश करता है।

गुजरात में 226 करोड़ रुपए के संदिग्ध क्रिप्टो नेटवर्क का पर्दाफाश, कई आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी

गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर स्थित साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने टेररिस्ट फंडिंग नेटवर्क, इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क और डार्क वेब से जुड़े 226 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इसी के साथ साइबर पुलिस ने 'डर्टी क्रिप्टो' को यूएसडीटी में बदलने वाले गैंग के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर संजय केशवलाल, पुलिस अधीक्षक, साइबर अपराध ने बताया कि आजकल बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी), सीआईडी क्राइम और रेलवे, डॉ के लक्ष्मी नारायण राव और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीआईजी), बिपिन अहीर ने सख्त और गहन कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुसार एसपी, डॉ राजदीप सिंह झाला और एसपी संजय केशवाला और एसपी विवेक भेड़ा ने अलग-अलग टीमें बनाई। उन्होंने ह्यूमन सोर्स और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से इस पूरे मामले में 10 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। क्राइम में फिलहाल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टेक्निकल यूनिट ने क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन और उसके ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह नेटवर्क डार्क वेब पर नशीली दवाओं की बिक्री, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी संगठनों की फंडिंग में शामिल पाया गया है।

इन सभी आरोपों को मद्देनजर रखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में बताए गए क्रिप्टो वॉलेट सब्बीर अली सरानी नाओ की जांच के दौरान पता चला कि उसके छोटे बेटे हदीरजा शब्बीर अली सरानी और दोस्त मोहम्मद जमीन अब्बास अली जिगर नाओ ने एक-दूसरे की मदद से सब्बीर अली सरानी नाओ की केवाईसी डिटेल्स हासिल कीं और (डर्टी क्रिप्टो) का वॉलेट खोला और गैर-कानूनी फंडिंग की। आरोपियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड 2023 के सेक्शन 111(2)(बी), 153, 61 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के सेक्शन 66(सी) और 66(डी) के तहत एक ऑर्गनाइज्ड गैंग बनाने, फाइनेंशियल चैनलों के जरिए आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने की साजिश रचने और एक दोस्त देश की सुरक्षा के खिलाफ काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड शिकायत दर्ज की गई है। इसी के साथ साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने जनता से अपील की है कि आप अपने बैंक अकाउंट किराए पर न दें। अनजान लोगों को कुछ कमीशन या लालच की आड़ में अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल और इसमें ट्रांजैक्शन न करने दें। ऐसे किराए के अकाउंट का गलत इस्तेमाल ड्रग्स, साइबर फ्रॉड या टेररिस्ट फंडिंग जैसे गंभीर और देश विरोधी अपराधों के लिए किया जा सकता है, जिसमें अकाउंट होल्डर कानूनी मुश्किल में भी पड़ सकता है।

हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में भारत का पहला ई85 फ्यूल किया लॉन्च

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से चिंतित नई दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए राहत देने वाली खबर है। उन्हें अब सीएनजी से सस्ता पेट्रोल मिलेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक विशेष पेट्रोल ई-85 फ्यूल को लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया

मंच 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ, हरित एवं ऊर्जा सुरक्षित भारत की विजन से प्रेरणा लेकर आज दिल्ली में फ्लैक्स फ्यूल पर चलने वाले वाहनों के लिए दिल्ली के इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर ई85 ईंधन का ऐतिहासिक उद्घाटन किया। उन्होंने आगे कहा कि ये ना केवल भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि किसानों की अतिरिक्त आय का साधन भी है।

इस पहल से हमारे ऊर्जादाताओं के जीवन में खुशहाली और उन्नति बनी रहेगी। पुरी ने आगे कहा, ई-85 फ्यूल को लॉन्च किया गया है...ई-85 फ्यूल एक क्रांतिकारी कदम है। इसकी शुरूआत के लिए 50-100 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे...दिसंबर 2026 तक इनकी संख्या में 500 तक बढ़ोतरी होगी, जो दिसंबर 2027 के अंत तक 5000 तक संख्या पहुंचेगी...। उन्होंने कहा कि इसका खर्च सामान्य फ्यूल से 20 रुपये कम है...हम कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी की नंबर प्लेट भी अलग हो...। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में सीएनजी की कीमत 83.09 रुपये प्रति किलो थी, तो ई85 पेट्रोल प्रति लीटर 82.12 रुपये में उपलब्ध था। वैसे ये पेट्रोल सामान्य वाहनों के उपयोग के लिए नहीं है। ये ए85 वाहनों के लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि इस विशेष पेट्रोल में 85 फीसदी तक ईथेनाल मिला है। फिलहाल दिल्ली में ऐसे वाहनों की संख्या न के बराबर है, क्योंकि वाहन कंपनियों ने हाल में इस नए वर्ग की गाड़ियों को बाजार में उतारना शुरू ही किया है।

विदेशी मुद्रा भंडार 93.8 करोड़ डॉलर बढ़ा

एजेंसी

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार गत 29 मई को समाप्त सप्ताह में 93.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 682.321 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले, लगातार दो सप्ताह में विदेशी मुद्रा का देश का भंडार 15.6 अरब डॉलर घटा था। गत 22 मई को समाप्त सप्ताह में इसमें 7.511 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गयी थी। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 29 मई को समाप्त सप्ताह में स्वर्ण भंडार 2.186 अरब डॉलर घटकर 112.60 अरब डॉलर रह गया। यह पांच महीने का इसका

निचला स्तर है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में आलोच्य सप्ताह में 3.116 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गयी। यह 29 मई को 546.148 अरब डॉलर पर रहा। इसमें अमेरिकी डॉलर के अलावा जापानी येन, यूरो और ब्रितानी पाउंड को भी शामिल किया जाता है। इनके मूल्य का आंकलन डॉलर के मुकाबले संदर्भ दर के आधार पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार के अन्य घटकों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि 80 लाख डॉलर बढ़कर 4.826 अरब डॉलर पर रहा। विशेष आहरण अधिकार 18.747 अरब डॉलर पर लगभग स्थिर रहा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज सुबह जारी बयान में कहा था कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत अच्छी स्थिति में है।

उतार-चढ़ाव के बाद लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कटौती करने और महंगाई की तेज रफ्तार का अनुमान लगाने, आईटी और मेटल सेक्टर में जोरदार बिकवाली होने तथा कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी। शुरुआती कारोबार में खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में और मजबूती आई। हालांकि यह मजबूती अधिक देर तक टिक नहीं सकी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मॉनिटरी पॉलिसी के साथ ही महंगाई और ग्रोथ से जुड़े अपने अनुमानों का खुलासा करने के बाद बाजार में बिकवाली का दबाव बन गया, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक लुढ़क कर लाल निशान में पहुंच गए। पूरे दिन शेयर बाजार में लिवालों और बिकवालों के बीच खींचतान चलती रही, जिसकी वजह से दोनों सूचकांकों की चाल भी लगातार ऊपर नीचे होती रही। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.16 प्रतिशत और निफ्टी 0.21 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए।

आज दिन भर के कारोबार के दौरान मीडिया, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर के शेयरों में जम कर खरीदारी होती रही। इसके अलावा बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और हेल्थकेयर इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए। दूसरी ओर, एनर्जी, टेलीकॉम और आईटी सेक्टर में आज लगातार बिकवाली होती रही। इसी तरह मेटल, ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, टेक और कैपिटल गुड्स इंडेक्स भी गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी आज दबाव बना रहा, जिसके कारण निफ्टी का मिडकैप इंडेक्स 0.35 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ आज के कारोबार का अंत किया।

आज शेयर बाजार में आए उतार चढ़ाव के बावजूद स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 461.59 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 461.45 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 14 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,399 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,056 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,138 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 205 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,999 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1384 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,615 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 13 शेयर बढ़त के साथ और 17 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 23 शेयर हरे निशान में और 27 शेयर लाल निशान में बंद हुए।

बीएसई का सेंसेक्स आज 269.93 अंक की मजबूती के साथ 74,629.94 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही बाजार में लिवालों और बिकवालों के बीच खींचतान शुरू हो गई, जिससे इस सूचकांक की चाल में उतार-चढ़ाव होने लगा। खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स 357.56 अंक की तेजी के साथ 74,717.57 अंक तक पहुंचा। वहीं बिकवाली का दबाव बनने पर इसने 371.26 अंक टूट कर 73,988.75 अंक के स्तर तक गोता भी लगाया। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 116.67 अंक की कमजोरी के साथ 74,243.34 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

जेनजी आंदोलन पर मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के खिलाफ अदालत जायेंगे ओली

एजेंसी
काठमांडू। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले नेपाल के विपक्षी दल यूएमएल (एमाले) ने जेनजी आंदोलन मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के खिलाफ अदालत जाने का फैसला लिया है। जेनजी आंदोलन के दौरान गत वर्ष 8 और 9 सितंबर को हुई घटनाओं की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। इस पर पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने आयोग की सिफारिशों पर असंतोष व्यक्त किया। पार्टी ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट तथ्यात्मक, कानूनी और विश्लेषणात्मक दृष्टि से गंभीर प्रश्नों के घेरे में है। यूएमएल ने विशेष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आयोग की सिफारिश पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संचार मंत्री की प्रत्यक्ष भूमिका, प्रत्यक्ष आदेश अथवा किसी प्रकार की आपराधिक जिम्मेदारी स्थापित करने में असफल रही है। इसके बावजूद रिपोर्ट राजनीतिक निष्कर्षों की ओर झुकते हुए कार्रवाई की सिफारिश करती दिखाई देती है, जो अपने आप में गंभीर विरोधाभास और औचित्यहीन है।

शी जिनपिंग 8-9 जून को जाएंगे उत्तर कोरियाः सरकारी मीडिया

मास्को)। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के निमंत्रण पर 8-9 जून को उत्तर कोरिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे।कोरियाई केंद्रीय समाचार एजेंसी (केसीएनए) ने यह जानकारी दी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी गत 9-10 अप्रैल को प्योंगयांग की यात्रा पर गये थे।किम जोंग उन ने जापान के खिलाफ युद्ध में चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर गत वर्ष 2-4 सितंबर के दौरान विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति जिनपिंग के निमंत्रण पर चीन की यात्रा की थी।

पूर्व राजदूत शंकर शर्मा ने कहा- रवि लामिछाने के भारत दौरे से बढ़ा संबंधों में भरोसा

काठमांडू। भारत में नेपाल के निवर्तमान राजदूत डॉ. शंकर शर्मा ने राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने की भारत यात्रा को नेपाल-भारत संबंधों के प्रति विश्वास को और मजबूत करने वाला बताया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के निमंत्रण पर नई दिल्ली पहुंचे लामिछाने ने प्रधानमंत्री मोदी सहित भारतीय नेताओं के साथ हुई अपनी मुलाकातों को वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक और उपयुक्त बताया है। राजदूत शर्मा का मानना है कि इस यात्रा ने नेपाल को भारत के साथ लंबे समय से लंबित द्विपक्षीय मुद्दों पर कूटनीतिक संवाद आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। शर्मा के अनुसार भारत में लामिछाने और उनके प्रतिनिधिमंडल को दिया गया सम्मान यह संकेत देता है कि नई दिल्ली नेपाल के साथ गहन सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि काठमांडू को इसे अपने राष्ट्रीय हितों को कूटनीतिक माध्यमों से आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि लामिछाने की यह यात्रा एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में हुई थी, लेकिन इससे यह स्पष्ट हुआ है कि भारत नेपाल के उभरते राजनीतिक नेतृत्व के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीमा विवाद तथा अन्य संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दों को राजनीतिक सद्भावना यात्रा के दौरान उठाने के बजाय औपचारिक सरकार-से-सरकार स्तर की वार्ताओं के माध्यम से ही सुलझाया जाना चाहिए। निवर्तमान राजदूत ने कहा कि लामिछाने की भारत यात्रा सफल और सार्थक रही। उनके अनुसार भारत ने नेपाल के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित करते हुए रेड कार्पेट स्वागत किया और भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर सकारात्मक संदेश दिया है।

बांग्लादेश में अवामी लीग की नेता सेलीना हयात को देररात जेल से रिहा किया गया

ढाका (बांग्लादेश)। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की दिग्गज नेता और नारायणगंज सिटी कारपोरेशन की पूर्व मेयर सेलीना हयात 'आइवी' को जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार हुई सेलीना की रिहाई पूर्व स्पीकर शिरीन शार्मिन चौधरी के बाद अवामी लीग के किसी बड़े नेता को मिली दूसरी बड़ी राहत है। प्रोथोम अलो अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सेलीना हयात को एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। उन्हें बुधवार रात लगभग 10:15 बजे गाजीपुर की काशिमपुर सेंट्रल महिला जेल से रिहा किया गया।

रात करीब 12:30 बजे वह नारायणगंज के देवभोग इलाके में स्थित अपने घर पहुंचीं। उनकी रिहाई की खबर मिलने के बाद रात 11:00 बजे से ही उनके घर के बाहर रिश्तेदार, समर्थक और शुभचिंतक जुटने लगे। लंबे समय तक जेल में बंद रहने के बाद उनकी वापसी पर लोगों ने राहत की सांस ली। सेलीना ने घर पहुंचने पर सबसे पहले देश की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैं न्यायपालिका की बहुत आभारी हूं और सरकार को भी धन्यवाद देती हूं। मुझे उम्मीद है कि एक ऐसी मानवीय सरकार बनेगी जो सभी को साथ लेकर चलेगी। जेल में मेरे जैसी कई महिलाएं हैं जो बेगुनाह हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाएगी।

इबोला के कारण स्पेन में डीआर कांगो का प्री-वर्ल्ड कप मैत्री मैच रद्द, कांगो ने जताई आपत्ति

एजेंसी
मैड्रिड। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने स्पेन के अधिकारियों के मैत्री मैच रद्द करने के फैसले की आलोचना की। नौ जून को चिली के खिलाफ होने वाला प्री-वर्ल्ड कप मैत्री मैच अफ्रीकी देश में चल रहे इबोला प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया। यह मैच दक्षिणी स्पेन के ला लि?निया डे ला कॉन्सेप्सियन में खेला जाना था, लेकिन मंगलवार को शहर के मेयर जुआन फ्रैंको ने घोषणा की कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण मैच नहीं होगा। फ्रैंको ने कहा, 'मैंने नौ जून को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और चिली के बीच होने वाले मैच पर रोक लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।' उन्होंने बताया कि ला लिनिया की स्थानीय स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख की रिपोर्ट में साफतौर पर सलाह दी गई थी कि संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए इस मैच की मेजबानी नहीं की जानी

चाहिए। डीआर कांगो की टीम विश्व कप अभियान की तैयारी के लिए बेल्जियम में एक सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर प्रशिक्षण कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 26 खिलाड़ियों में से कोई भी खिलाड़ी कांगो में नहीं खेलता है और न ही सीधे वहां से बेल्जियम के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचा है। हालांकि, सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्य और संभव है कि कुछ प्रशंसक वहां से आए हों। एजेंसी के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से आयोजित एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, डीआर कांगो के संचार मंत्री पैट्रिक मुयाया ने इस स्थिति पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा, 'स्पेन के अधिकारियों के साथ हमें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने फैसला किया है कि हमारी राष्ट्रीय टीम का दूसरा निर्धारित मैच इबोला के कारण नहीं खेला जा सकता।' मुयाया ने कहा, 'मेरा मानना है कि हमारा कोई भी खिलाड़ी किंशासा या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में नहीं खेलता। वे सभी लगभग तीन हफ्तों से बेल्जियम में हैं और विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के फैसले को भेदभावपूर्ण माना जा सकता है।' विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इबोला एक गंभीर और अक्सर जानलेवा बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों (जैसे फल खाने वाले चमगादड़, साही और अन्य प्राइमेट) से इंसानों में फैल सकता है।

जांच रिपोर्ट में नेपाल के पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरुङ को क्लीन चिट, दोबारा मंत्री बनाए जाने की चर्चा

एजेंसी
काठमांडू। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरुङ के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री बालेन शाह को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में गुरुङ के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।

पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने 22 अप्रैल को पद से इस्तीफा दे दिया था। उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने, अपनी संपत्ति के स्रोत का खुलासा न करने तथा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट के साथ निवेश संबंध रखने के आरोप लगे थे। इन आरोपों की जांच के लिए सरकार ने 11 मई को पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश अच्युत प्रसाद भण्डारी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था।समिति में महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारी शोभाकान्त पौडेल और उप-न्यायाधिवक्ता अच्युत मणि न्यौपाने सदस्य के रूप में शामिल थे।समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री बालेन शाह को सौंप दी। गुरुङ के इस्तीफे के बाद से गृह मंत्रालय मंत्रीविहीन है और वर्तमान में प्रधानमंत्री बालेन शाह स्वयं इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पीएमओ का कहना है कि जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष और सिफारिशों के आधार पर सरकार सुदन गुरुङ को पुनः गृह मंत्री नियुक्त करने की संभावना पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो आरोपों के कारण पद छोड़ने के लगभग डेढ़ महीने बाद उनकी सरकार में वापसी हो सकती है।

जेलेंस्की का पत्र पढ़ चुके हैं पुतिन, पश्चिमी देशों से बातचीत के लिए तैयारः क्रेमलिन

एजेंसी
मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा भेजा गया खुला पत्र प्राप्त कर उसे पढ़ लिया है। यह जानकारी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दी। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टीएएस समाचार एजेंसी के अनुसार, पेसकोव ने सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान एक साक्षात्कार में बताया कि राष्ट्रपति पुतिन को जेलेंस्की के पत्र और उस पर विभिन्न विश्व नेताओं की प्रतिक्रियाओं की भी जानकारी दी गई है। अपने खुले पत्र में जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन युद्ध को सीधे संवाद के जरिए समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा, 'यूक्रेन हमारे और आपके बीच सीधे संवाद के माध्यम से इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है। मैं एक बैठक का प्रस्ताव रखता हूं।' जेलेंस्की ने सुझाव दिया कि इस तरह की वार्ता की मेजबानी स्विट्ज़रलैंड, तुर्किए या अरब देशों में से कोई देश कर सकता है। उन्होंने बैठक की एक स्पष्ट तिथि तय करने और बातचीत की अवधि के दौरान पूर्ण युद्धविराम लागू करने की भी पेशकश की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि वास्तविक और पूर्ण युद्धविराम ही सार्थक बातचीत की शुरुआत का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान से जुड़े हालिया घटनाक्रम इस बात को और महत्वपूर्ण बनाते हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता पेसकोव ने कहा कि रूस अब भी वार्ता प्रक्रिया फिर से शुरू करने की उम्मीद रखता है। उन्होंने कहा,

'हमें उम्मीद है कि मौजूदा गतिरोध अंततः टूटेगा और संवाद के नए प्रयास शुरू होंगे। हम अभी भी मौजूदा माध्यमों के जरिए अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क में हैं।' पेसकोव ने यह भी कहा कि रूस बातचीत से पीछे नहीं हट रहा है और राष्ट्रपति पुतिन संवाद के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, 'यदि यूरोपीय देश रूस के साथ संवाद न करने की अपनी नीति छोड़ दें, तो उन्हें केवल फोन उठाकर बातचीत शुरू करनी होगी।' हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यूक्रेन संघर्ष बेहद जटिल है और इसका समाधान आसानी से नहीं निकलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर दुनिया की नजर बनी हुई है। ऐसे समय में जेलेंस्की के सीधे संवाद के प्रस्ताव और पुतिन की बातचीत के प्रति कथित तत्परता को संभावित कूटनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिकी कांग्रेस में ईरान युद्ध की लागत और असर को लेकर तीखी बहस, जवाब मांग रहे डेमोक्रेट

एजेंसी
वॉशिंगटन । अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति में ट्रंप प्रशासन के ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर तीखी बहस हुई। वित्त वर्ष 2027 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट (एनडीएए) पर चर्चा के दौरान इस युद्ध की लागत, रणनीति और अमेरिका की वैश्विक प्राथमिकताओं पर इसके असर को लेकर गहरे मतभेद सामने आए। कांग्रेस में हुई इस बैठक के दौरान डेमोक्रेटिक लॉमेकर्स ने बार-बार प्रशासन की युद्ध संबंधी नीति पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि कांग्रेस और अमेरिकी जनता को अब तक इस युद्ध की वास्तविक लागत और इसके रणनीतिक परिणामों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। प्रतिनिधि सेठ मौल्टन ने कहा कि कांग्रेस को यह पता होना चाहिए कि इस युद्ध पर कितना खर्च हो रहा है। उनका कहना था कि जब तक पूरी वित्तीय जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक प्रतिनिधि अपनी निगरानी और जवाबदेही की जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा सकते।

मौल्टन ने प्रस्ताव रखा कि रक्षा विभाग ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों पर हुए खर्च का विस्तृत हिसाब पेश करे। उन्होंने कहा कि बढ़ती ईंधन कीमतों और आर्थिक अनिश्चितता के बीच अमेरिकी जनता पारदर्शिता की हकदार है।

प्रतिनिधि जेसन क्रो ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह कर्तव्य है कि वह जाने कि इस युद्ध पर करदाताओं का कितना पैसा खर्च हो रहा है।

समिति में शीर्ष डेमोक्रेट एडम स्मिथ ने कहा कि पेंटागन से अधिक पारदर्शिता के बिना लॉमेकर प्रभावी निगरानी नहीं कर सकते।

स्मिथ ने कहा, 'हमें वास्तव में यह जानने की जरूरत है कि कितना खर्च हो रहा है और पैसा कहां जा रहा है।' उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन के ईरान संबंधी बड़े उद्देश्यों को लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। वहीं रिपब्लिकन लॉमेकर्स ने प्रशासन के कदमों का जोरदार बचाव किया।

समिति के अध्यक्ष माइक डी. रोजर्स ने इस संघर्ष को 'पसंद से चुना गया युद्ध' बताए जाने का विरोध किया और कहा कि सैन्य कार्रवाई ने ईरान की क्षमताओं को काफी कमजोर कर दिया है। रोजर्स ने कहा, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने उन पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया है।' उनका दावा था कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीति अमेरिका को ऐसे समझौते के करीब ले आई है जो ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं से पैदा होने वाले खतरे को स्थायी रूप से खत्म कर सकता है।

कांग्रेस सदस्य जो विल्सन ने भी प्रशासन का बचाव करते हुए कहा कि ईरान लंबे समय से एक खतरा रहा है और अमेरिकी हितों तथा क्षेत्रीय सहयोगियों की सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई जरूरी थी।

मानवाधिकार उल्लंघनों के बीच पाकिस्तान को जीएसपी-प्लस लाभ देने पर सवालों के घेरे में यूरोपीय संघ

एजेंसी
वॉशिंगटन । मानवाधिकारों के कथित गंभीर उल्लंघनों के बावजूद पाकिस्तान को व्यापारिक रियायतें जारी रखने को लेकर यूरोपीय संघ (ईयू) की आलोचना तेज हो गई है। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और विशेषज्ञों ने आरोप लगाया है कि 2014 से लागू विशेष व्यापारिक व्यवस्था के बावजूद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों पर अपेक्षित प्रगति करने में विफल रहा है। ब्रुसेल्स स्थित मानवाधिकार संगठन सीमाओं के बिना मानवाधिकार (एचआरडब्ल्यूएफ) ने पाकिस्तान को दिए गए जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेज प्लस (जीएसपी-प्लस) दर्जे को 'ईयू और पाकिस्तान के बीच खराब सौदा' बताया है। संगठन का कहना है कि जब तक मानवाधिकारों के क्षेत्र में ठोस सुधार नहीं दिखता, तब तक इस सुविधा को निलंबित किया जाना चाहिए। तुर्की मूल की पत्रकार उज़े बुलुत ने अमेरिकी मीडिया मंच पीजे मीडिया में प्रकाशित लेख में लिखा है कि 2014 में समझौता लागू होने के बाद से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय

मानवाधिकार मानकों को लागू करने में सार्थक प्रगति दिखाने में नाकाम रहा है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव देश के ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय पर पड़ा है। लेख के अनुसार, पाकिस्तान की आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी दो प्रतिशत से भी कम है, लेकिन उन्हें सामाजिक और संस्थागत स्तर पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। भीड़ हिंसा, ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग, आर्थिक भेदभाव, अपहरण, यौन हिंसा और जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं।

बुलुत ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद ईयू पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान करता रहा है। पाकिस्तान को जीएसपी-प्लस योजना के तहत यूरोपीय बाजार में 66 प्रतिशत से अधिक टैरिफ श्रेणियों पर शुल्क-मुक्त या रियायती पहुंच प्राप्त है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति का उल्लेख करते हुए लेख में लाहौर की 14 वर्षीय ईसाई किशोरी निशा बीबी के मामले का भी जिक्र किया गया है। परिवार और कानूनी प्रतिनिधियों के अनुसार, उसका कथित रूप से अपहरण कर जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया और विवाह कराया गया। पीड़िता के पिता अब्बास मसीह ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी एक मुस्लिम परिवार में घरेलू सहायक के रूप में काम करते समय लापता हो गई थी।

लेख में कहा गया है कि पाकिस्तान में कानूनी, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं, जिसके कारण ईसाई लड़कियां अपहरण, जबरन धर्मांतरण और जबरन विवाह जैसी घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील रहती हैं।

नेपाल में शुरू हुई उबर की सेवा, काठमांडू में हुआ औपचारिक शुभारंभ

एजेंसी
काठमांडू। वैश्विक राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म उबर ने शुक्रवार से नेपाल में अपनी सेवाओं का आधिकारिक शुभारंभ कर दिया है।कंपनी ने एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान नेपाल में अपने संचालन की शुरुआत की घोषणा की। आधिकारिक शुरुआत के साथ उबर ने नेपाल के राइड-हेलिंग बाजार में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत हुई है तथा यात्रियों को ऐप आधारित परिवहन का एक नया विकल्प उपलब्ध हुआ है। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने नेपाल में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी साझा की और इसे नेपाली बाजार में उबर की औपचारिक एंट्री बताया। कंपनी ने संकेत दिया है कि सेवा के संचालन क्षेत्र, उपलब्ध सुविधाओं और अन्य विशेषताओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी आने वाले दिनों में सार्वजनिक की जाएगी।

नेपाल में उबर के आगमन को देश के डिजिटल परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प

और सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें पर्यटन मंत्रालय के सचिव और अवसंरचना विकास मंत्रालय के सचिव सहित अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल थे।

क्या अमेरिका में भी आलोचकों की आवाज दबा रहा चीन? कांग्रेस की सुनवाई में सख्त कानून की मांग तेज

एजेंसी
वॉशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस में चीन सरकार की उन कोशिशों पर फिर से सवाल उठाए गए, जिनके जरिए वह अपनी सीमाओं के बाहर भी आलोचकों की आवाज दबाने की कोशिश करती है। गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस में हुई एक सुनवाई में सांसदों, राज्य अधिकारियों और लोकतंत्र कार्यकर्ताओं ने बताया कि चीन अब सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में डराने-धमकाने, निगरानी और दबाव बनाने की बढ़ती हुई मुहिम चला रहा है। यह सुनवाई कांग्रेसनल एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना (सीईसीसी) में हुई, जो तियानमेन स्क्वायर नरसंहार की 37वीं बरसी के दिन आयोजित की गई थी। इसमें सांसदों ने कहा कि चीन के तरीके अब घरेलू दमन से आगे बढ़कर 'ट्रांसनेशनल रिप्रेशन' यानी सीमाओं के बाहर जाकर दमन करने की वैश्विक रणनीति बन गए हैं। सुनवाई की शुरुआत में सह-अध्यक्ष सांसद क्रिस स्मिथ ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) कई तरह के तरीके इस्तेमाल कर रही है। इनमें चीन में परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेना, लोगों की निजी जानकारी सार्वजनिक करना (डॉक्सिंग), स्पाइवेयर का इस्तेमाल, डीपफेक वीडियो, हांगकांग से जुड़े इनाम (बाउंटी) और अमेरिका में भी अवैध पुलिस स्टेशन चलाना शामिल है। सह-अध्यक्ष सांसद जिम मैकगवर्न ने कहा कि चीन दुनिया में ट्रांसनेशनल दमन करने वाला सबसे बड़ा देश है। उन्होंने फ्रीडम हाउस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 से अब तक 319 ऐसे मामले सामने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को 'ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पॉलिसी एक्ट' पास करना चाहिए, जिससे इस मुद्दे की कानूनी परिभाषा तय हो सके और सरकार की प्रतिक्रिया मजबूत हो। सुनवाई में सबसे ध्यान खींचने वाली गवाही आर्थर लियू की थी, जो पहले चीन में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता थे और 1989 के तियानमेन आंदोलन के बाद चीन छोड़कर अमेरिका के कैलिफोर्निया में बस गए थे। लियू ने बताया कि उन्हें लगा था कि अमेरिका आने के बाद राजनीतिक उत्पीड़न खत्म हो गया है, लेकिन 2021 में सब बदल गया, जब एफबीआई ने उन्हें बताया कि एक चीनी एजेंट उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है और उनकी बेटी, ओलंपिक फिगर स्केटर एलिसा लियू, के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है, ताकि 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स से पहले दबाव बनाया जा सके। लियू ने कहा, 'एफबीआई ने मुझसे सावधान और सतर्क रहने को कहा।' उन्होंने बताया कि एजेंटों ने उन्हें यह भी बताया कि संदिग्ध जासूस उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है, उनकी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा सकता है और उनके पासपोर्ट की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकता है। लियू ने कहा, 'मुझे अपनी बेटी एलिसा की सुरक्षा को लेकर बहुत डर लग रहा था, जब वह अमेरिका की तरफ से चीन में प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही थी।'

भारत दौरे से लौटे रवि लामिछाने बोले- कूटनीतिक मुद्दों का समाधान शोर मचाकर नहीं, चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए

एजेंसी
काठमांडू। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने कहा है कि जिन मुद्दों का समाधान कूटनीतिक माध्यमों से किया जाना चाहिए, उन्हें सार्वजनिक प्रचार-प्रसार या अनावश्यक शोर-शराबे के बजाय सावधानीपूर्वक और चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। भारत की पांच दिवसीय यात्रा पूरी कर नेपाल लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए लामिछाने ने कहा कि कूटनीतिक मामलों को 'ढोल पीटकर' नहीं निपटाया जा सकता। त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थल (टीआईए) पर नेपाल-भारत सीमा विवाद से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि वह संवाद को सुगम बनाने और कूटनीतिक माध्यमों से समाधान खोजने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी मुद्दे को कूटनीति के माध्यम से और कूटनीतिक चैनलों को सक्रिय करके हल किया जाए। ऐसे विषय न तो ढोल पीटकर और न ही ऊंची आवाज़ में सार्वजनिक बयानबाजी करके सुलझाए जा सकते हैं। जहां भी देशहित में कार्रवाई की आवश्यकता हो, उसे शांतिपूर्वक और चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।' लामिछाने ने कूटनीति को एक संवेदनशील और जिम्मेदारीपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि यदि देश की सबसे भरोसेमंद राजनीतिक शक्ति ही कूटनीति की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को नहीं समझेगी, तो वह कूटनीतिक मामलों में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकेगी। उन्होंने कहा कि लोकप्रियता हासिल करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन समस्याओं का समाधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। 'कूटनीति की भी अपनी अलग-अलग अवस्थाएं और चरण होते हैं। नेपाल ने परंपरागत रूप से ऐसे मामलों को उचित कूटनीतिक प्रक्रिया के जरिए संभाला है और आज भी वही तरीका अपनाया जा रहा है,' उन्होंने कहा। लामिछाने भारत की पांच दिवसीय यात्रा पूरी कर नेपाल लौटे। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत गए थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेता नितिन नवीन तथा अन्य वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की। भारत प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर से भी हुई।

पीओके में हड़ताल से निपटने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करने का फैसला

एजेंसी
मुजफ्फराबाद (पीओके) पाकिस्तान। संघीय सरकार ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में नौ जून को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के विरोध प्रदर्शन (हड़ताल) के आह्वान के मद्देनजर अतिरिक्त सिविल आर्म्ड फोर्स और पुलिस कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया गया है। स्थानीय सरकार ने पर्यटकों के लिए चेतावनी भी जारी है। न्यूज की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 1,000 पंजाब रेंजर्स और 2,000 फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के जवानों को पीओके भेजा जाएगा।। इसके अलावा, पीओके में इस्लामाबाद पुलिस के 2,000 अधिकारी और सिंध पुलिस के 1,000 अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। पीओके सरकार ने पर्यटकों के लिए चेतावनी भी जारी की है। पीओके सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रांत में प्रवेश करने से बचें और पांच जून से 20 जून के बीच गैरजरूरी यात्रा न करें। जो लोग पर्यटन या अन्य उद्देश्यों से इस क्षेत्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करने की सलाह दी गई है। सरकार ने परामर्श में कहा कि विरोध प्रदर्शन की संभावना के कारण लोगों को यात्रा करने से बचना चाहिए। जो पर्यटक और तीर्थयात्री अभी इस क्षेत्र में हैं, उन्हें पांच जून की शाम तक यहां से चले जाने का निर्देश दिया गया है।

हिज्बुल्लाह ने इजरायली विमानों पर दागीं मिसाइलें, आईडीएफ ने किया दावा

एजेंसी
तेल अवीव। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने हिज्बुल्लाह की ओर हमले किए जाने का दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि हिज्बुल्लाह की ओर से इजराइली वायुसेना के विमानों को निशाना बनाकर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी गईं। हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और न ही विमान को कोई नुकसान पहुंचा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मिसाइल दागे जाने के बाद किर्यत शमोना शहर और लेबनान सीमा के पास उत्तर-पूर्वी इजरायल के आठ गांवों में हवाई हमले के सायरन बज उठे, जिससे हजारों निवासी सुरक्षित स्थानों (शेल्टर) की ओर भागने लगे। ये घटनाक्रम तब सामने आया, जब इजरायल और लेबनान ने बुधवार को वाशिंगटन में त्रिपक्षीय बातचीत के बाद युद्धविराम लागू करने पर सहमति व्यक्त की थी।

इसी बीच, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने अमेरिका के साथ बातचीत में लेबनान का इस्तेमाल

सौदेबाजी के तौर पर करने के लिए ईरान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने हिज्बुल्लाह के महासचिव नईम कासिम की भी आलोचना करते हुए कहा कि लेबनान के लोग युद्ध से थक चुके हैं और शांति से जीवन जीना चाहते हैं।

आउन ने ये बातें एक साक्षात्कार में कहीं, जिसे लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को जारी किया।

गुरुवार को, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बयान में कहा कि अमेरिका और इजरायल के साथ 8 अप्रैल के समझौते को स्वीकार करने के लिए ईरान की मुख्य शर्त लेबनान सहित सभी मोर्चों पर पूर्ण युद्धविराम थी। साक्षात्कार में आउन ने कहा, 'यह आपका देश नहीं है, यह हमारा देश है।' उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय ताकतों की ओर से अपने हितों को साधने के लिए लेबनान का इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है, जबकि लेबनान के नागरिक मौत, विस्थापन और तबाही के रूप में संघर्ष के परिणाम भुगत रहे हैं।

राष्ट्रपति आउन ने कहा कि लेबनान और इजरायल के बीच संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका बातचीत ही है। उन्होंने कहा कि लेबनान के राज्य और सरकार को हिज्बुल्लाह के मुद्दे को घरेलू स्तर पर हल करना होगा। इसके लिए समूह की सशस्त्र मौजूदगी के मूल कारणों से निपटना होगा, जिसमें इजरायल का लेबनान के क्षेत्र से हटना और संघर्ष का अंत शामिल है। आउन ने कहा कि सभी समुदायों और क्षेत्रों के लेबनानी लोग दशकों के संघर्ष से थक चुके हैं। समझौते का विरोध करने और सड़क पर विरोध प्रदर्शनों के जरिए सरकार गिराने की धमकी देने वाले कासिम के बयानों पर टिप्पणी करते हुए आउन ने कहा, 'वे लेबनान के लोग हैं, न कि नईम कासिम के लोग।'

page 1 and 8 June 7_page 1 Mar 25 final ds.qxd 6/7/2026 1:14 AM Page 2

स्थानीय समाचार

मेला माता खीर भवानी की तैयारियों की समीक्षा

श्रीनगर, 06 जून। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज माता खीर भवानी मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, ताकि श्रद्धालुओं के लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। बैठक में गांदरबल, श्रीनगर, कुपवाड़ा, कुलगाम और अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नरों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे। बैठक में कश्मीरी पंडित संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और परिवहन, आवास, टेंट, मोबाइल शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छता और रोशनी जैसी आवश्यकताओं पर सुझाव दिए। डिविजनल कमिश्नर ने सभी विभागों को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तुलमुला मंदिर परिसर में बहने वाली नहर की सफाई और डीसिल्टिंग कराने के निर्देश दिए।

श्रद्धालुओं के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए परिवहन व्यवस्था और बस सेवाओं के समन्वय पर जोर दिया गया।

उन्होंने साफ-सफाई और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।

एसएसपी गांदरबल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सीपीसीओ अमित शर्मा ने बारामूला में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस की समीक्षा की

बारामूला, 06 जून। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी (सीपीसीओ) अमित शर्मा ने आज बारामूला में बैठक कर जनगणना 2027 के तहत चल रहे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस की समीक्षा की।

बैठक में अधिकारियों ने जनगणना की तैयारियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी।

अमित शर्मा ने फील्ड स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि जनगणना कार्य पूरी ईमानदारी और पेशेवर तरीके से किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को समन्वय बनाए रखने और सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे फर्जी कॉल या संदेशों से सावधान रहें और किसी भी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी को साझा न करें।

उन्होंने कहा कि जनगणना के लिए केवल अधिकृत कर्मियों को ही जानकारी दी जाए।

उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1855 पर संपर्क किया जा सकता है।

सीपीसीओ अमित शर्मा की मीडिया से बातचीत (जनगणना 2027)

बारामूला, 06 जून। सीपीसीओ अमित शर्मा ने जनगणना 2027 को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि जनगणना देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास है, जो नीति निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया डिजिटल तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सही जानकारी देकर सहयोग करें। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि वे जनगणना के बारे में जागरूकता फैलाएं। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

डिव कॉम कश्मीर ने मुहर्रम-उल-हराम व्यवस्थाओं की समीक्षा की

श्रीनगर, 06 जून। आगामी मुहर्रम-उल-हराम से पहले, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अनशुल गर्ग ने आज वरिष्ठ अधिकारियों और हितधारकों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें घाटी भर में धार्मिक रस्मों और जुलूसों के शांतिपूर्ण और सुचारू आयोजन के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में इस पवित्र महीने के दौरान आवश्यक नागरिक, बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आकलन किया गया, जिसमें विभागों के बीच समन्वय और समुदाय प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के दौरान विधायक बडगाम आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने शिया बहुल क्षेत्रों में कई मुद्दों को उठाया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ध्यान देने की मांग की। उन्होंने निर्बाध बिजली और पेयजल आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत और मैकडमाइजेशन, स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता तथा प्रमुख धार्मिक स्थलों पर चिकित्सा कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की आवश्यकता पर जोर दिया।

उत्सव की भावना बिगाड़ने वालों का वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद होगा : सीएम योगी

गोंडा, 6 जून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले की स्थिति अब कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा, 2015-16 में गोंडा में दुर्गा पूजा के दौरान दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी। उस समय मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन में बाधा डाली जाती थी और रामलीला कार्यक्रमों में भी व्यवधान पैदा किया जाता था। त्योहारों और उत्सवों से पहले ही अशांति शुरू हो जाती थी। 2017 से पहले सत्ता में बैठे लोग दंगाइयों और अपराधियों के सामने झुकते थे और राज्य में महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था।

शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपये और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपये की कुल 516 करोड़ रुपये की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया और विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 卐असुरक्षा के माहौल में निवेश नहीं बढ़ सकता। 2017 से पहले राज्य पहचान संकट से जूझ रहा था, युवा परेशान थे, किसान संघर्ष कर रहे थे और महिलाएं तथा बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस करती थीं। आज सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के राज्य के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों, 826 विकास खंडों, 762 नगर निकायों, लगभग 14 हजार वार्डों और 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच रहा है।卐

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडा के युवा ऊर्जावान हैं, किसान मेहनती हैं, महिलाएं प्रतिभाशाली हैं और यहां के कारीगरों ने देश और दुनिया में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में गोंडा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उसे वह विकास नहीं मिल पाया जिसका वह हकदार था।

उन्होंने कहा कि अब लोग आत्मीयता के साथ मिलते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यदि भगवान श्रीराम का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो अयोध्या से सटे गोंडा के लोगों से मित्रता जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 कर्मियों की भर्ती में गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर के युवाओं को भी नियुक्तियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि जब वह नियुक्ति पत्र देने से पहले भर्ती सूची देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि गोंडा के युवाओं को बिना भेदभाव नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की ताकत से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने राम मंदिर आंदोलन को करीब से देखा और पिछली सरकारों के समय की कठिनाइयों का सामना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक बिना भेदभाव पहुंचाया जा रहा है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज और समेकित विद्यालय जैसे सपने अब साकार हो रहे हैं उन्होंने लोगों से अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने की अपील करते हुए कहा कि अच्छे चुनाव अच्छे परिणाम लाते हैं जबकि गलत चुनाव लोगों को परेशानियों में डाल देते हैं।

डीसी ने पुलवामा में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की

पुलवामा, 06 जून। उपायुक्त (डीसी) पुलवामा डॉ. बशारत कयूम ने आज प्रशासनिक परिसर पुलवामा में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एचएडीपी), जम्मू और कश्मीर कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स प्रोजेक्ट (जेकेसीआईपी), प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई), नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन (एनडीएलएम), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और अन्य किसान कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

किसानों के लिए केकेजी की विविधीकरण और समय पर ऋण सहायता पर जोर

बैठक में कृषि, बागवानी, पशुपालन, भेड़ पालन और मत्स्य पालन विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों, आवेदन की स्थिति, लाभार्थी कवरेज, ऋण लिंकिंग, व्यय और योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

डीसी ने एचएडीपी और जेकेसीआईपी के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत इकाइयों की स्थापना में तेजी लाने और स्थापित इकाइयों की नियमित निगरानी करने पर जोर दिया ताकि योजनाओं के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

डीसी कुलगाम ने खेत बचाओ अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की

कुलगाम, 06 जून। 'खेत बचाओ अभियान' के तहत ब्लॉक पाहलू में किसानों के लिए जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में ब्लॉक के विभिन्न गांवों के किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

उपायुक्त कुलगाम शहजाद आलम ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कृषि भूमि की सुरक्षा और वैज्ञानिक खेती अपनाने पर जोर दिया ताकि सतत कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि कृषि योग्य भूमि की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं और भूमि को अन्य उपयोगों में बदलने से रोकना जरूरी है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को 'खेत बचाओ अभियान' के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी, जिसमें कृषि भूमि की रक्षा, सतत खेती को बढ़ावा, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना शामिल है।

मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

कार्यक्रम के अंत में किसानों के साथ संवाद सत्र हुआ जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए।

डीसी बांदीपोरा ने आर्मी गुडविल स्कूल का दौरा किया, छात्रों की प्रस्तुति की सराहना की

बांदीपोरा, 06 जून। उपायुक्त बांदीपोरा इंदु कंवल चिब ने आर्मी गुडविल स्कूल बांदीपोरा का दौरा किया और छात्रों व शिक्षकों से बातचीत की।

उन्होंने हाल ही में आयोजित जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) पदयात्रा में छात्रों की भागीदारी और राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान की प्रस्तुति की सराहना की। डीसी ने कहा कि छात्रों ने अपने प्रदर्शन से कार्यक्रम को विशेष बनाया और सभी से प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने स्कूल को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया।

छात्रों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उपराज्यपाल ने किश्तवाड़ के प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर में दर्शन किए

जम्मू, 6 जून। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज किश्तवाड़ जिले के सरकूट क्षेत्र में स्थित प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए और पूजा-अर्चना की।

उन्होंने इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शांति, समृद्धि, विकास और सभी लोगों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

अपने दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों द्वारा रखी गई मांगों को गंभीरता से सुना।

उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि मंदिर के पास स्थित तालाब के पुनर्निर्माण, सफाई और सुधार के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि इस धार्मिक स्थल की सुंदरता और पवित्रता बनी रहे।

उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति और धरोहर से जुड़ी रह सकें।

इस अवसर पर उपराज्यपाल के साथ जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनिल शर्मा, किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार, उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने उपराज्यपाल को क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी भी दी।

बंगाल को एक लाख करोड़ की सौगात, दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन समेत 61 नई रेल परियोजनाओं का ऐलान

कोलकाता, 06 जून। पश्चिम बंगाल में रेल बुनियादी ढांचे को नई गति देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार ने लगभग एक लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं में दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, 102 अमृत भारत स्टेशन, 61 नई रेल परियोजनाएं, 538 फ्लाईओवर और अंडरपास तथा कोलकाता मेट्रो के बड़े विस्तार जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।

इन परियोजनाओं की घोषणा शनिवार को नबान्न (राज्य सचिवालय) में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद की गई। बैठक में रेलवे और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इसे राज्य में रेल विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच नए सहयोगात्मक दौर की शुरुआत माना जा रहा है।

बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली को वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। परियोजना के पूरा होने पर उत्तर बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और यह लगभग छह घंटे तक सीमित हो सकता है। इससे क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के 102 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इनमें से 10 स्टेशनों पर कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष स्टेशनों पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा राज्यभर में 538 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा, जिससे रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।

रेल मंत्रालय ने 61 नई रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से करिमपुर, जालंगी, लालगढ़, गोपीबल्लभपुर, नयाग्राम, हीली, सागर द्वीप और सुंदरबन जैसे क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना है, जो लंबे समय से बेहतर रेल संपर्क की मांग कर रहे हैं।

कोलकाता मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को भी इस पैकेज में प्रमुखता दी गई है। अगले पांच वर्षों में मेट्रो के लिए 60 नई पीढ़ी की ट्रेनों को शामिल किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और अधिक क्षमता उपलब्ध होगी। साथ ही डानकुनी से सूरत तक प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई, जिसे औद्योगिक विकास और माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ का रिकॉर्ड रेल बजट आवंटित किया है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार रेल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देगी और सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

भद्रवाह में चौथे लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन

भद्रवाह, 06 जून (हि.स.)। दो दिवसीय चौथे लैवेंडर महोत्सव 2026 का शुभारंभ आज भद्रवाह सरकारी डिग्री कॉलेज में 卐लैवेंडर वैश्विक स्तर पर卐 विषय के साथ हुआ।

इस भव्य आयोजन का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया।

सीएसआईआर-भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान द्वारा आयोजित यह महोत्सव लैवेंडर मिशन की उल्लेखनीय सफलता और चिनाब घाटी क्षेत्र में आई बैंगनी क्रांति का जश्न मनाता है।

किसानों, छात्रों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और आम जनता की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर में आई बैंगनी क्रांति के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि भद्रवाह ने लैवेंडर की खेती के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान बनाई है और दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस क्षेत्र से लैवेंडर-थीम वाली एक झांकी प्रदर्शित की गई थी।

मूल्यवर्धन, कृषि स्टार्टअप, उद्यमिता और वैश्विक बाजार संबंधों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं और किसानों की सफलता लैवेंडर की खेती की अपार क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने भद्रवाह में लैवेंडर पर्यटन के उदय पर भी प्रकाश डाला और लैवेंडर-आधारित उत्पादों की वैश्विक उपस्थिति को और बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से सरकारी डिग्री कॉलेज भद्रवाह को विरासत संस्थान घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने जिले भर में देखी गई बेहतर सड़क संपर्क और समग्र विकासात्मक प्रगति की सराहना की।

अपने स्वागत भाषण में सीएसआईआर-आईआईआईएम जम्मू के निदेशक डॉ. जबीर अहमद ने भद्रवाह में लैवेंडर की खेती की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और इस क्षेत्र को भारत की लैवेंडर क्रांति का केंद्र बताया। उन्होंने एक पायलट परियोजना को राष्ट्रव्यापी सफलता की कहानी में बदलने में सीएसआईआर-आईआईआईएम जम्मू, किसानों, उद्यमियों और हितधारकों के समन्वित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि लगभग 5,000 किसान लैवेंडर आंदोलन से जुड़ चुके हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध भद्रवाह लैवेंडर को आने वाले वर्षों में अधिक अंतरराष्ट्रीय पहचान और बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी।

इस महोत्सव में प्रदर्शनियां, प्रदर्शन, खरीदार-विक्रेता संवाद, स्टार्टअप शोकेस और निजी हितधारकों और सरकारी विभागों द्वारा लैवेंडर आधारित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन शामिल था। लैवेंडर मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सीएसआईआर-भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान और एक निजी क्षेत्र के भागीदार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।